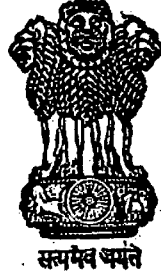


पुस्तकालय

①
3133
18/3/2011



असंशोधित

11 0 MAR 2011

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग 2-कार्यवाही-प्रश्नोत्तर रहित)

प्रतिवेदन शाखा
वे.सं.प्र.सं. ५५१ दिनांक १७/३/११

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । वित्तीय कार्य लिये जायेंगे ।

वित्तीय कार्य

अध्यक्ष : ग्रामीण कार्य विभाग की अनुदान की मांग पर वाद विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा इसके लिये तीन घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है । इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिये समय दिया जायेगा ।

जनता दल यूनाईटेड	:	८४ मिनट
भारतीय जनता पार्टी	:	६७ मिनट
राष्ट्रीय जनता दल	:	१६ मिनट
कांग्रेस पार्टी	:	४ मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी	:	३ मिनट
सी०पी०आई०	:	१ मिनट
निर्दलीय	:	<u>५ मिनट ।</u>
कुल		१८० मिनट ।

माननीय प्रभारी मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

डॉ० भीम सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि ग्रामीण कार्य विभाग के संबंध में ३१ मार्च, २०१२ को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिये १६,३४,५०,३७,०००/- (सोलह अरब चौंतीस करोड़ पचास लाख सैंतीस हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : इस मांग पर माननीय सदस्य श्री सम्राट चौधरी, श्री अख्तरूल इमान, श्रीमती ज्योति रश्मि एवं श्री अवधेश कुमार राय से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो व्यापक हैं । जिनपर सभी माननीय सदस्य विचार विमर्श कर सकते हैं ।

माननीय सदस्य, श्री सम्राट चौधरी का प्रथम प्रस्ताव है । अतः माननीय सदस्य श्री सम्राट चौधरी अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री सम्राट चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस शीर्षक की मांग १०/- रुपये से घटाई जाय राज्य सरकार की ग्रामीण कार्य नीति पर विचार विमर्श करने के लिये ।

हमारी पार्टी की ओर से माननीय सदस्य राम लषण राम रमणजी अपनी बातों को रखेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री राम लषण राम रमणजी ।

श्री राम लषण राम रमण : राम लखन राम रमण ।

अध्यक्ष : लषण ।

श्री राम लषण राम रमण : लखन है भई । आप खडशास्त्री लिखते हैं तो कौन ख लिखते हैं जरा बोलिये ।

मुझे ध्यान है और इसीलिये मैं कहता हूँ कि जो कुछ बोलूंगा, सब मालूम है, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा ।

महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमारजी अपार बहुमत से सत्ता हासिल किये, अच्छा करना चाहते हैं यह मैं भी जानता हूँ, प्रतिपक्ष में हूँ इसलिये सिर्फ निंदा करने की जरूरत नहीं है, जो त्रुटियाँ हैं सरकार की उसको गिनाने की आवश्यकता है । इसीलिये ये हमारा पिछले दिनों काफी बिहार का दुर्भाग्य रहा है जो भारत सरकार का इस वक्त रिपोर्ट है उसमें मनरेगा में वित्तीय वर्ष २०१०-११ में कुल उपलब्ध राशि २१६० करोड़ है और खर्च की गयी राशि ११४४ करोड़ है लेकिन बजट भाषण में यह कहा गया है कि १६५३ करोड़ खर्च है तब भी कितना अंतर है इसमें ।

अध्यक्ष : राम लषणजी, ग्रामीण कार्य विभाग पर चर्चा है ।

श्री राम लषण राम रमण : जी मैं आ रहा हूँ उसी पर । ग्रामीण कार्य विभाग भी इसमें है ।

अध्यक्ष : डिमांड है ग्रामीण कार्य विभाग का ।

श्री रामलषण राम "रमण":- ग्रामीण विकास विभाग की योजना मद में जैसे मनरेगा २४७२ करोड़ रुपये रखा गया था, उपलब्धता के विरुद्ध मात्र ५० प्रतिशत राशि आज खर्च हो पायी। यह हिन्दुस्तान टाईम्स में जो छपा हुआ है हुजूर, दिनांक १४.२.२०११ के मुताबिक मात्र इसमें ०.०२ प्रतिशत काम पूरा हुआ, उपलब्ध राशि दो हजार करोड़ के विरुद्ध एक लाख ८८ हजार ५५१ योजनाएँ लिये गये थे, चालू वित्तीय वर्ष में ३१२० करोड़ रुपये व्ययकरण करने का प्रावधान था, जिसमें ८ लाख ९१ हजार बी०पी०एल० परिवारों को इंदिरा आवास बनाया जाना था, परन्तु उसमें भी ५० प्रतिशत से कम राशि खर्च हो पायी, ८ लाख ९१ हजार इंदिरा आवास बनाने के विरुद्ध अभी तक मात्र तीन लाख ११ हजार इंदिरा आवास बनाये जा सके हैं। उसी तरह ३१२० करोड़ रुपया योजना मद में जिसमें २२७६ करोड़ रुपया ही खर्च किया गया। अभी इस मामले में मैं यह बताना चाहता हूँ महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार जब पहले बनी थी, तो प्रथम कैबिनेट की बैठक में राज्य के पदाधिकारियों को स्पष्ट कहा था कि चाहे वह पक्ष के विधायक हो, चाहे विपक्ष के विधायक हो, सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास किया जायेगा लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि दिनांक १५ जून, २०१० को राज्य मंत्रिपरिषद् ने मेरे विधान सभा क्षेत्र मधुबनी जिला के रामपट्टी, खैरा, भदुआर के समीप कमला नदी पर एक पुल बनाने हेतु लगभग २३ करोड़ रुपया की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी। पुल बनाने का निर्माण निगम को सौंपा गया, नवार्ड ने भी इसकी स्वीकृति दे दी, पैसा भी उपलब्ध करा दिया गया हुजूर लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि प्रशासनिक स्वीकृति पत्र पुल निर्माण निगम को अब तक नहीं सौंपा गया है, अभी तक वहाँ कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है सिर्फ इसलिए कि चूंकि उस क्षेत्र से मैं विधायक बना हूँ। एक नया क्षेत्र बना है राजनगर और अंधराठाढ़ी, दो ब्लॉक उसमें है, अंधराठाढ़ी यानि हमारे क्षेत्र के सदस्य वोटर हमारे माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री नीतीश मिश्रा जी भी हैं, झंझारपुर से लेकर और बाबूबरही क्षेत्र तक बीच में २० किलोमीटर के बीच कमला नदी पर कोई पुल नहीं है, कभी भी जाना पड़ता है हमलोगों को या तो झंझारपुर क्षेत्र होकर जायेंगे या बाबूबरही क्षेत्र होकर जायेंगे, दोनों प्रखंडों के बीच कोई पुल नहीं है, यह पुल जब सरकार ने स्वीकृत किया, बड़ी खुशी हुई आम जनता को, हमलोगों को भी बड़ी खुशी हुई, अब हम आग्रह करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हस्तक्षेप करें और तुरत जो आपने स्वीकृति दी है उस पुल की, उस पुल को बनाना शुरू करावे।

क्रमशः

श्री राम लक्षण राम "रमण" (क्रमशः) महोदय, योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में हम कहना चाहेंगे कि बिहार की जो स्थिति है, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, करें। पिछले दिनों नेमप्लेट का पहाड़ खड़ा किया गया। फीता काटकर योजनाओं का नाम दिया गया। सभी इंजीनियर्स और ठीकेदार नेमप्लेट लेकर अपने-अपने क्षेत्र में भागे। नेमप्लेट लगायें। आज उस में स्थिति यह है कि उस की समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी करावें। स्थिति यह है कि जैसे चार स्टेज योजना के होते हैं : एस्टीमेट, इम्प्लीमेंट, मेजरमेंट और तब फाइनल पेमेंट। यहां १२ आना काम होता है, सिर्फ ४ आना नहीं होता है। एस्टीमेट बनता है, मेजरमेंट भी होता है, फाइनल पेमेंट भी होता है, यह तीन स्टेज में १२ आना हुआ, सिर्फ इम्प्लीमेंट बाकी रह जाता है। जांच करानी चाहिए और तमाम इंजीनियर्स और ठीकेदार और बड़े-बड़े लोगों का, जो बड़ा-बड़ा भवन बनता है, वह भी जो बाकी रह जाता है, वह पटना में आ कर बन जाता है। अट्टालिकायें बन जाती हैं। वैसे मुख्य मंत्री जी ने जरूर कहा है कि सब के भवनों को हम जप्त करेंगे जो नाजायज हैं। यह बड़ी खुशी की बात है।

महोदय, भारतीय नृत्य कला मंदिर में जो बाल संसद बच्चों का आयोजित हुआ था, उसमें बच्चों ने कहा, आज के अखबार में जो निकला है कि सर, स्कूल निर्माण में ३ नंबर की घटिया इंट लगती है। अब इन बच्चों के अर्तनाद को कौन सुनेगा? क्या उन बच्चों की आह किसी पर नहीं पड़ेगी। सुनना चाहिए। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, इन्होंने विधायक निधि को समाप्त किया। यह बड़ी अच्छी बात हुई। हमलोग जब सरकार में थे तो खास तौर पर हम भी चाहते थे, हमारे नेता श्री सिद्धीकी साहब भी चाहते थे। अंततः जब समाप्त करने ही वाले थे, हमलोग नहीं कर सके। हालांकि हमारे माननीय मंत्री श्री रमई बाबू अभी यहां पर मौजूद नहीं हैं। जब कैबिनेट से निकले थे तो लिफ्ट पर इन्होंने इतना गुस्से में कहा कि हम क्या बतावें। लेकिन अच्छा हुआ। आप ने उस पैसे को मुख्य मंत्री क्षेत्र विकास योजना के नाम से नई योजना आप ने प्रारंभ की है। लेकिन हरेक जगह पर आप का नाम खुदा होगा। तो २०६ जो माननीय विधायक हैं, सत्तापक्ष के, उन का तो काम चल जायेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के केअर ऑफ में भी।

व्यवधान

एक मिनट। कहने तो दिया जाय। तो उनका काम तो चल जायेगा। मगर जो प्रतिपक्ष के सिर्फ ३७ विधायक हैं, उनका नाम कैसे होगा?

व्यवधान

जबर्दस्ती कैसे लिख दिया जायेगा? महोदय, वैसे लोग कहते हैं कि :-

सत्ता की गोद से निकली हजारों गलियारे,

लेकिन मैं कहता हूं सत्ता की गोद से हजारों गलियां तो निकली है,

मगर अफसोस है कि कोई गली गरीब के गांव तक जाता ही नहीं।

सत्ता की गोद से निकली हजारों गलियारे,

गरीब के गांव तक कोई गली जाती ही नहीं ॥

महोदय, ४० प्रतिशत जो हमारे क्षेत्र में ग्रामीण सड़कें कच्ची पड़ी हुई हैं। ५० प्रतिशत सड़कें जिसका खरंजा या पक्कीकरण हुआ, वे इतनी जर्जर अवस्था में है, अब तो सभी लोग यह कहने लगे हैं कि सरकार अपना रोड़ा उठा कर ले जाय। इसलिये कि वे पैरों में भी गड़ते हैं।

क्रमशः

टर्न-23/सत्येन्द्र/10-3-11

श्री राम लषण राम 'रमण'(क्रमशः) अभी 206 माननीय विधायक कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में सब कुछ हुआ, माननीय विधायकों का क्षेत्र 206 में बहुत ज्यादा काम हुआ,मगर अभी तक दिल पर हाथ देकर माननीय विधायकगण कहें कि उनके क्षेत्रों में आपलोग रिश्तत से परेशान नहीं है, क्या यह सही नहीं है कि घूस लेने वाले तमाम अफसर यह नहीं कहते कि हमको अपने से ऊपर वाले को देना पड़ता है, छात्रों के आय प्रमाण-पत्र,आवासीय प्रमाण-पत्र,जाति प्रमाण-पत्र आदि में घूस नहीं देना पड़ता है,ऐसे लोग बड़े भाग्यशाली होंगे, जिनको बिना पैसे का सर्टिफिकेट मिल गया होगा। महोदय,

बड़ी दया आती है इनपर, मैं जानू इनका हाल कैसा है,
भय मजबूरी बनी एकता,पिंजड़े के तोते जैसा है।

महोदय,इन्दिरा आवास योजना बैंकों में लाभान्वितों के नाम एक साल, दो साल पहले खाते खोले गये,जिनलोगों ने पांच हजार,10 हजार रू0 तक घूस नहीं दिया,उनलोगों के खाते में इस वक्त तक पैसा नहीं जमा हुआ है,उदाहरणस्वरूप आप राजनगर और अंधराटाढ़ी प्रखंड की जांच करवा लें कि अबतक उनके पैसे उनके खाते में क्यों नहीं जमा हुए,सैकड़ों की संख्या ऐसे लोग हैं जो गरीब नहीं जानते कि हमारे नाम पर प्रखंड में इन्दिरा आवास का पैसा उठा लिया गया,न घर बना न किसी को पता है कि वो पैसा कहां गया इसलिए हम इसकी जांच कराने की मांग करते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो या चाहे राहत वितरण का कार्य हो हजारों जायज लोग अभी छूटे हुए हैं,महोदय..

अध्यक्ष: माननीय सदस्य,आप सदन के प्ररिष्ठ सदस्य हैं,आज डिमांड है
ग्रामीण कार्य विभाग पर।

श्री राम लषण राम 'रमण' लेकिन ग्रामीण विकास भी तो इसमें है। महोदय,राजनगर विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र में राजनगर रामपट्टी से कैथाही-कोईलख तक सड़क-5 कि0मी0जर्जर है जिसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। भगवानपुर-मैलाम चौक तक, ये 8 कि0मी0 सड़क है जो दो प्रखंडों के 8 पंचायतों को जोड़ती है,एक राजनगर की तीन पंचायतें और फिर अंधराटाढ़ी की पंचायतों को ये सड़क जोड़ती है। रॉटी मुख्य सड़क से पलिवार ग्राम से चकदह ग्राम तक,शिविपट्टी चौक से मधुबनी टोल होते हुए करहिया तक,पटवारा चौक से सहोड़वा गांव तक,राजनगर करहिया पंचायत पूर्वी में जीवछ चौधरी क घर से लेकर जगदीश चौधरी के घर तक,राजनगर प्रखंड की शिविपट्टी पंचायत मं मधुबनी टोल होस्पीटल से मुशहरी होते हुए जटानी मुस्लीम टोल तक,राजनगर-करहिया पश्चिमी पंचायत लालापुर ब्रह्मस्थान से गौड़ी मेरन ब्रह्मस्थान तक,राजनगर परिहारपुर पंचायत में परिहारपुर मंडल चौक से करहिया पश्चिम प्रधानमंत्री सड़क एवं पुल का निर्माण,राजनगर प्रखंड की रघुनीटेहट पंचायत में अहमदा एवं हरिनगर सड़क पर मिट्टी खरंजा एवं आर0सी0सी0पुलिया,राजनगर-कोईलख महादेव मंदिर से चौधराना मुशहरी तक

टर्न-23/सत्येन्द्र/10-3-11

..

पक्कीकरण,अंधराठाढ़ी प्रखंड के भंगद्वार से मैलाम चौक तक पक्कीकरण,अंधराठाढ़ी मैलाम पंचायत के मध्य विद्यालय सिजौल से मैलाम होते हुए गंगद्वार हटियागाछी पक्की सड़क से तिलई मुस्लीम एवं ठाकुर टोल तक(कमशः)

टर्न-24/10.3.2011/बिपिन

श्री राम लषण राम'रमण': कमशः हम यह कहना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि जन-संपर्क विभाग के माध्यम से एवं पर्चा छपवा कर यह प्रचारित करावें कि कोई भी व्यक्ति किसी को घूस न दे, प्रखंड में, लोगों का हौसला बुलंद होगा, लोग अँडेंगे। मुख्यमंत्री कहेंगे कि हमको खबर करो, अगर कोई घूस मांगता है तो। जनता का मनोबल ऊंचा होगा। अन्यथा लोग समझेंगे कि -

गरीबों को हक दो, यह नारा सही है,
मगर हक दिलाना गँवारा नहीं।'।

महोदय, प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी निदेश दें। यह मैं चाहता हूं कि यह सर्टिफिकेट दाखिल करे बी0डी0ओ0 और सी0ओ0...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री राम लषण राम'रमण': बस, लास्ट है महोदय। तो, मुख्यमंत्री जी निदेश दें कि तुम तीन महीने के अंदर लिखित सर्टिफिकेट दो कि हमारे क्षेत्र के अंदर न तो कोई वृद्धा पेंशन के जायज लोग छूटे हुए हैं, न इंदिरा आवास के जायज लाभान्वित छूटे हुए हैं, और किसी प्रकार का जो विकास का कार्य है, गरीबों को देना है, वह कोई छूटा हुआ नहीं है, यह सर्टिफिकेट दे। अगर उसमें छूटा हुआ कोई होगा, अगर प्रतिनिधि, चाहे मुखिया, कोई भी अगर जांच करके देंगे कि नहीं साहब, इन्होंने सर्टिफिकेट दिया है, वह गलत है, इतने लाभान्वित अभी भी छूटे हुए हैं, तो मुख्यमंत्री जी सजा का निदेश दें। यही कह कर मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं।

हाँ, हमारे मंत्री जी, हमारे जिला के प्रभारी भी हैं। ये प्रयास करते हैं। हम इनके कायल हैं।

श्री राम सेवक सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा 16अरब 24करोड़ 50लाख...

अध्यक्ष : राम सेवक जी, एक मिनट। देखिये माननीय मंत्री जी...

श्री हरि प्रसाद साह, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य भाषण दे रहे थे, शायद पुरानी बात उन्हें याद नहीं होगा, नहीं होगा। मैं याद दिला देना चाहता हूं...व्यवधान..हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, अपनी कुछ बात सुना देते हैं सिद्धिकी भाई, कि हमलोग पचास आई कहां से शुरू किया था। वही याद दिला रहे हैं माननीय सभी सदस्यों को। पचास साल के बाद जो यह परिस्थितियां बनी, सरकार की और जो दिया है लाभ, उसके बारे में कहना चाहता हूं। ...व्यवधान.. अच्छा आदमी की बात मैं नहीं कह रहा हूं। मैं जनहित की बात कर रहा हूं। हमलोगों का प्रोग्राम था, सोसलिस्ट पार्टी का प्रोग्राम था। वह जमाना था कांग्रेस का और वहां थे देश के प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू। उस जमाने में डा० राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर, आचार्य नरेन्द्र देव, अरूणा आसफ अली, एस० सुब्बाराव, सिमरन कसूरी, मृणाल गोरे, ऐसे हमलोगों के नेता थे। हम नारा लगाया करते थे कि -

'बिना कफन का मुर्दा जलता,
इस कांग्रेसिया राज में,
अरे! गरीब का बेटा पढ़ नहीं पाता,

इस कांग्रेसिया राज में,
जब नेहरू रंग बदलता है
तो देश को धोखा देता है।'

कहने का मतलब है हमलोगों का कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उसको इम्प्लीमेंट किहिन, और दे रहे हैं पैसा पंद्रह सौ रूपया । गरीब के बेटे के लिए नारा लगाया था हमलोग कि गरीब का बेटा पढ़ नहीं पाता, इस कांग्रेसिया राज में, तो हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी पढ़ाने का काम कर रहे हैं । इतना ही नहीं, उसके साथ-साथ जो आपस में मत-भिन्नता था, ऊंचा नीचा का सवाल था दलित, गरीब का सवाल था, उन बच्चों के आधार पर हमलोगों ने, हमारी सरकार ने पोषाक योजना चलाया । साईकिल योजना चलाई हमारी सरकार ने और उन बच्चों को साइकिल हम दे रहे हैं । कहां कहीं नीचा, ऊंचा की बात है, अगड़ा-पिछड़ा का सवाल है और दूसरी बात कहते थे कि - '

संसोपा ने बांधी गांठ,
पिछड़ पारे सौ में साठ ।'

थपथपी।

जब हमारी सरकार बनी तो हमलोग पंचायत के राज्य मंत्री बने, तब हमलोगों ने पिछड़ों का, खासकर महिलाओं का, महिलाओं के प्रति बार-बार डा0 लोहिया बोला करते थे ...
क्रमशः

श्री हरि प्रसाद साह, मंत्री : ...क्रमशः... क्या वे सुख भोगती थीं ? घर के बाहर महिलाएँ निकलें और देश के....(व्यवधान) जवाब की बात मैं नहीं कह रहा हूँ माननीय सदस्य, कुछ बात को आप याद करें जमाने की बात, उस जमाने में हम कहा करते थे....

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, नेता विरोधी दल : कर्पूरी जी जो आपके यहाँ मछली-भात खाते थे, उसके बारे में भी कहिये न !

श्री हरि प्रसाद साह, मंत्री : हाँ खाते थे, वह भी कह दें ! हमलोग नारा लगाया करते थे बड़े-बड़े जमींदारों के खिलाफ कि

"धनवा-धरती बँटकर रहेगी, भूखी जनता अब न सहेगी,

अरे ठहरो-ठहरो पूंजीवाद, आ रहा है समाजवाद ।"

उस समय का हमलोगों का नारा था । इसीलिये मैं यह कहना चाहूँगा, उसको आपलोग याद कीजिये ।

"धनवा-धरती बँटकर रहेगी, भूखी जनता अब न सहेगी,

अरे ठहरो-ठहरो पूंजीवाद, आ रहा है समाजवाद ।"

"जबतक भूखा इंसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा ।"

"अरे पेट है खाली मारे भूख, बन्द करो दावों का लूट ।"

"राष्ट्रपति का बेटा हो या हो भंगी का संतान,

सबकी शिक्षा-दीक्षा एक समान ।"

"अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा ।"

अंग्रेज यहाँ से चला गया, उनको भी जाना है ।

"राष्ट्रपति का बेटा हो या हो भंगी का संतान,

सबकी शिक्षा-दीक्षा एक समान ।"

वह हमलोगों का नारा था और

"लूटने वाला जायेगा, नया जमाना आयेगा और नीतीश भाई राज चलायेंगे ।"

(थपथपी)

श्री राम लषण राम "रमण" : मैंने कोई सरकार की निन्दा नहीं की, कुछ त्रुटियों की ओर हमने ध्यान दिलाया था और मैंने शुरू में कहा था कि जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा । आपने जिन बातों की चर्चा की, उस लड़ाई का एक हिस्सा मैं भी रहा हूँ । यह माथा उड़ा उसी में, लड़कर आता रहा हूँ ।

श्री हरि प्रसाद साह, मंत्री : माथा तो उड़ा जरूर लेकिन लाभ क्या दिया ?

अध्यक्ष : रमण जी, माथा नहीं उड़ा है.....

श्री राम लषण राम "रमण" : अभी मैंने आपकी कोई निन्दा नहीं की, मैं आपका भी कायल हूँ, मैं अच्छी बात कह रहा हूँ, मैंने सरकार की कोई निन्दा नहीं की है । मैं कहता हूँ कि यह जनतंत्र का इतना बड़ा महल, जिस महल को हमारे नेताओं ने अपनी शहादत देकर महात्मा गाँधी के नेतृत्व में इसको हासिल किया और सत्तासीन लोगों ने क्या दिया लोगों को कि आजादी का अर्थ क्या हुआ तो कहा है-

"डरो नहीं कुछ भी करने से चूँकि तुम आजाद हो,
आजादी का अर्थ है जिसमें सबका जिन्दाबाद हो ।
क्या गलत और क्या सही, इसकी नहीं परवाह हो,
जो जहाँ पर कार्यरत हो, सबका घर आबाद हो ।"

न उसमें आप हैं, न उसमें हम हैं, हम यह नहीं कह रहे हैं, इसलिये
कहा - देखना पड़ेगा कि क्यों कर शीशे चूर हुये हैं, ये जनतंत्र का इतना बड़ा महल,
उसके शीशे क्यों कर चूर हुये, तो

"क्यों कर शीशे चूर हुये हैं, मैं भी ढूँढ़ूँ तु भी ढूँढ़ूँ,
था किस-किस हाथों में पत्थर, मैं भी ढूँढ़ूँ तु भी ढूँढ़ूँ,
सर ढाँके पर पैर खुले ना, क्यों कर हम होंगे मजबूर,
कद से लम्बी ऐसी चादर, मैं भी ढूँढ़ूँ तु भी ढूँढ़ूँ ।"

(थपथपी)

श्री हरि प्रसाद साह, मंत्री : इसी पर कहा है कि

"आचार नहीं बदला तो विचार बदलकर क्या होगा,
जब सारा मांझी पागल हो तो पतवार बदलकर क्या होगा ।"
"अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था,
हमारी किशती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था ।"

(थपथपी)

श्री राम लषण राम "रमण" : एक लाईन महोदय, यह हम कह रहे हैं आपसे, तमाम लोगों से कि - मेरा
एतराज यहाँ है कि

"केहु के घर में सहरी आ केहु खाय खातिर मरी, वाह रे !

केहु के घर में जरावे खातिर डिबिया ना आ केहु के पैखाना में जरी मरकरी, वाह रे !"

आप तो हमारे बड़े भाई हैं, हम भी साहित्यकार ठहरे और आप साहित्यिक
लहजे में बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ।

श्री प्रेम रंजन पटेल : अध्यक्ष महोदय, मैं भी व्यवस्था पर हूँ । व्यवस्था यह है कि :-

" दो बूढ़ा शेर को टकराते देखा ,
आज वीरान इनका घर देखा,
तो कई बार झांक कर देखा,
पांव टूट हुए नजर आयें,
एक ठहरा हुआ सफर देखा ।"

श्री श्याम बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम भी व्यवस्था पर बानी, तनी सुन ली । होली ह, होली ह, बुरा न माना होली ह । इन लोगों को विकास नइखे लौकित, का लौकित, कहियो न लौकित । इनका लौकित, का लौकित ।

(व्यवधान)

डॉ० इजहार अहमद : अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्ष : अवसर मिलेगा, आगे दिन मिलेगा, होली में अभी समय है ।

डॉ० इजहार अहमद : महोदय,

"अगर बादल यों ही गरजता रहेगा,
झमाझम यों ही पानी बरसता रहेगा,
तुम भी न सकोगी मुझसे और न हम भी सकेंगे तुमसे
मुलाकात के लिए दिल तरसता रहेगा । "

श्री राम लषण राम रमण : एक बात सर,

मेरी हक बातें भी गलत हैं,
लफ्ज मेरा हर शिकवा है,
आप करें गर लाख गलत भी,
पर दुःख की कोई बात नहीं है ।

श्री श्याम बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्ष : श्री श्याम बहादुर जी, बैठिए । माननीय सदस्य श्री राम सेवक सिंह जी ।

श्री राम सेवक सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा १६,३४,५०,३७,०००/- रु० के मांग के पक्ष में तथा विपक्ष द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद से अनेकों सरकारें आयी और गई लेकिन नवम्बर, २००५ के बाद जब बिहार की जनता ने माननीय नीतीश कुमार जी के हाथों में सत्ता सौंपा । उस अवधि के बाद ग्रामीण कार्य विभाग में यदि किसी सरकार में काम हुए या किसी के नेतृत्व में काम हुए तो उस व्यक्ति का नाम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार है । अभी विपक्ष के साथियों के साथ माननीय सदस्यों ने अपने-अपने तरह से अपनी बातों को रखने का काम किया । अनेकों विभाग में अनेकों कठिनाईयों के बारे में इन लोगों के माध्यम से बताया जाता है लेकिन पूर्व में भी २००५ से २०१० के बीच में भी हमलोग इन लोगों की बातों को सुनने

के लिए लालायित रहते थे कि आपलोगों के अवधि में यदि ग्रामीण कार्य विभाग में अमुक त्रुटियां हैं और उस त्रुटि को हमलोग इस तरह से इस विभाग में काम नहीं करते थे । हमारी सरकार की विधि अमुक थी तो इन लोगों के समय की विधि क्या थी। इन लोगों के समय की विधि यदि राज्य के सीमा से यदि उत्तर प्रदेश से हम बिहार में प्रवेश करते थे तो जहां टूटा हुआ सड़क मिलता था, वहां बिहार का सीमांकन का व्यक्ति अनुभव करता था कि अब हम बिहार के बोर्डर पर पहुंच चुके हैं, बिहार में प्रवेश कर चुके हैं । टूटी हुई सड़कों से बिहार की पहचान की जाती थी लेकिन उस टूटी हुई सड़कों को, उस खण्डहर को भरने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से ५ वर्षों में किया गया है । क्रमशः.....

श्री रामसेवक सिंह : क्रमशः.....माननीय विपक्ष के साथी सदन में भी विचित्र बोलते हैं। चुनाव के समय में क्या हुआ, चुनाव में जो भी विचित्र बातें रखी, हमारी सरकार के माध्यम से सड़कें अच्छी तरह बनीं, लेकिन इनके द्वारा क्या कहा गया, इनके द्वारा कहा गया कि सड़कों में अलकतरा नहीं, मोबिल से बन रही है। इनके द्वारा कहा गया कि अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिल रही हैं और भवन बन रहा है तो माननीय सदस्य बता रहे हैं कि अभी तीन नंबर का ईटा लग रहा है। आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूँ कि इनकी सरकार की अवधि में १५ साल में कितने भवन बने, कितने ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कें बनी और कितनी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से सड़कें बनी और उस समय के सड़कों की क्वालिटी क्या थी ? हमलोगों की सरकार के माध्यम से ग्रामीण कार्य विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से ५०० से ५११-वाले बसावट को मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से जोड़ने का प्रस्ताव ग्रामीण कार्य विभाग के माध्यम से हो रहा है। हम समझते हैं कि बिहार में २४३ जो विधान सभा क्षेत्र है, कोई माननीय सदस्य यहां खड़ा होकर बता दें कि किसी भी विधान सभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का कार्य नहीं हुआ हो, हर जगह पूरे बिहार के अनेक क्षेत्रों में सड़कों का जाल फैला हुआ है, सड़कों की प्रगति काफी मात्रा में हो रही है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से ग्रामीण कार्य विभाग के माध्यम से सड़क का काम सही तरीके से हो रहा है और सड़कों के रख रखाव के लिए भी सरकार ने पहले निर्णय लिया था कि पांच वर्षों के रख रखाव के लिए संवेदक की राशि से दस प्रतिशत सरकार के माध्यम से रोकी जाती है, ५ वर्ष के मेन्टेनेन्स के लिए, जितनी भी ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कें हैं उन सड़कों को सुदृढ़ ५ साल की अवधि तक रखने में हमारी सरकार सफल रही है। उसके साथ साथ भारत सरकार के माध्यम से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से, हमलोग चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव के समय में विचित्र स्थिति थी, उस समय हमारे कांग्रेस के साथी भी बैठे थे चुनाव के समय इन लोगों ने सोचा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में टेंडर होने के पहले रोड का हम समझते हैं कि रोड की जितनी लंबाई नहीं है उससे ज्यादा लंबाई इनलोगों के माध्यम से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए बोर्ड लगाने का प्रयास किया गया, लेकिन उसकी स्थिति क्या है। राशि भारत सरकार के माध्यम से नहीं आने के चलते उस रोड की स्थिति आज की तिथि में बिहार सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द काम हो, लेकिन राशि के आवंटन के अभाव में पूरे बिहार में हमारे क्षेत्र के साथ साथ सड़कों की स्थिति आज भी जिधर भी जाइये बहुत हमारी स्थिति सुधर गयी है। हम समझते हैं कि गोपालगंज जिला में या किसी विधान सभा क्षेत्र में चारों तरफ जाइये ग्रामीण कार्य विभाग, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मुख्यमंत्री सेतु योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत योजनाएं चल रही हैं और इन लोगों के समय में क्या हुआ, क्यों नहीं किये, इन लोगों को कौन व्यक्ति रोका, हम इस सदन के माध्यम से प्रतिपक्ष के नेता हमारे वरिष्ठ नेता हैं माननीय श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी जी इनसे भी हम आग्रह करेंगे कि हमलोग जो पांच वर्षों तक काम किये तो ५५ से संख्या आपकी हो गयी २२ और इसी तरह से आप

बोलते रहियेगा अंदर भी गलत बात, बाहर भी गलत बात तो अगली बार हम समझते हैं कि मुख्यमंत्रों का उड़न खटोला किसी क्षेत्र में नहीं जायेगा, हमलोगों को कोई भोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और २४३ के २४३ सीट अगली बार निश्चित रूप से एन०डी०ए० गठबंधन के पक्ष में जीतकर आयेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जो सुझाव दें वह सही सुझाव दें, जहां गड़बड़ी है, गड़बड़ी को सरकार निश्चित रूप से सुधार करेगी और जहां गड़बड़ी होगी इस सरकार में चाहे कोई भी परिवार का व्यक्ति हो वह उसके लिए छोड़ा नहीं जायेगा। हम गोपालगंज जिला के हथुआ विधान सभा क्षेत्र से आते हैं और उस विधान सभा क्षेत्र के पूर्व प्रतिपक्ष की नेता माननीय राबड़ी देवी जी का घर है। उनके समय में विचित्र बातें होती थी, ३०२ का मुजरिम थाना में बैठकर नेतागिरी करता था। मेरा मानना है कि हम जैसा करेंगे उसका फल हमें मिलेगा और हमारी जो भी खामी है, उस खामी को निश्चित रूप से रखें उसमें सरकार निश्चित रूप से सुधार करेगी। माननया अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने २०११-१२ में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से ३०० करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान ११०० कि०मी० सड़क निर्माण कराने का लक्ष्य रखा है। जबकि हमारी सरकार ने पिछले पांच वर्षों में ३३४९.४ कि०मी० सड़क का कालीकरण कराया है और इस कार्य पर १४६१.२१ करोड़ रुपया खर्च हुआ है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो एन०डी०ए० गठबंधन की सरकार चल रही है। सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वित्तीय वर्ष २०११-१२ में १३५०० कि०मी० सड़क बनाने का और ५००० करोड़ रुपया व्यय करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग का कहना है कि जो प्रधानमंत्री सड़क योजना में धीमी गति है, जो शिथिलता है, हम आपसे भी आग्रह करेंगे कि भारत सरकार से पत्राचार कर निश्चित समय पर जो राशि है उपलब्ध कराये ताकि जो सड़कें हमारी बननी है, निश्चित रूप से सड़कें बने और जल्द से जल्द हम सड़कें बना सकें। अध्यक्ष महोदय, आपके मध्यम से हम मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि गोपालगंज जिला के हथुआ विधान सभा क्षेत्र के प्रखंड उचकागांव के ग्राम सलेमपट्टी, असनन्द टोला, बलेसरा, बालाहाता, वृति टोला, धरनीहाता होते हुए सबैया हवाई पट्टी जानेवाली नारायणपुर उप वितरणी का पथ का कालीकरण कराने का प्रयास करेंगे। साथ ही गोपालगंज जिला के प्रखंड फुलवरिया के ग्राम पंचायत राजचमारी पट्टी के चमारी पट्टी पेनुएला मिश्र होते हुए लकड़ी बनवीरा जानेवाली पथ में जो गड़ढा हो गया है उसको बनवाने का काम करें। इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं ग्रामीण विकास मंत्री के ^{जुति आभार व्यक्त करता हूँ} धन्यवाद देता हूँ।

श्री सचिन्दर प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग तथा समाज कल्याण विभाग के द्वारा लाये गये बजट प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले मैं बिहार के दधिचि पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी जी और उनके साथ साथ इन चारों विभागों के मंत्री डा० भीम सिंह जी, आदरणीय नीतीश मिश्रा जी, आदरणीय हरिप्रसाद साह जी और श्रीमती आदरणीय परवनी अमानुल्लाह जी के प्रति केशरिया की ओर से बौद्ध नगर की केशरिया और केशरनाथ की भूमि केशरिया की ओर से सहृदय ^{आभार व्यक्त करता हूँ} धन्यवाद प्रकट करता हूँ

और सजदा प्रकट करता हूँ कि ऐसे लोगों के साथ केशरिया के मतदाता मालिकों ने मुझे भी काम करने के लिए इस विधान सभा में भेजा है। मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि बिहार की सरकार का कि जो सरकार पिछले पांच वर्षों से काम कर रही है और उसके काम के नीतियों के आधार पर आज इस पूरे बिहार में जो परिवर्तन आया है इस परिवर्तन को समझने और महसूस करने के लिए पूरा भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के प्रेस के साथी मीडिया के साथी और जो स्वतंत्र समीक्षक हैं, वे सभी समीक्षा कर रहे हैं कि अब बिहार के विकास की जो गति है बिहार के विकास का जो रफ्तार है, बिहार में जो विकास की हवा बह रही है यह करिश्माई नेतृत्व और इस नेतृत्व के साथ काम करनेवाले जो बिहार विधान सभा के सत्तापक्ष के माननीय सदस्यगण हैं और उनके नेतृत्व में काम करनेवाले आदरणीय और सम्मानीय मंत्री हैं, यह कैसी टेक्नीकल चतुराई के साथ इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि बिहार प्रगति और विकास के रास्ते पर इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है।

क्रमशः.....

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : ...क्रमशः ...

माननीय महोदय, ग्रामीण कार्य विकास के विषय में मैं कहना चाहता हूँ, हमलोग बिल्कुल गांव में रहनेवाले लोग हैं, किसान परिवार के लोग हैं, आज से ७-८-१० साल पहले ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की स्थिति जब हम देखते थे तो महसूस होता था कि शायद गड्ढे में यह सड़क है । अब तो कहीं कहीं सड़क में गड्ढा दिखायी पड़ता है लेकिन पहले पूरा का पूरा महसूस होता था कि गड्ढे में ही कहीं कहीं सड़क है । परिवर्तन हुआ है ग्रामीण कार्य विभाग ने वैसे गड्ढापूर्ण सड़कों को एक अच्छी सड़क के रूप में परिवर्तित किया है और सड़कों के माध्यम से बिहार को विकास देने की नयी दिशा और रोशनी प्रदान की है । महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत सरकार के माध्यम से शुरू किया गया था इस योजना को शुरू करनेवाले आदरणीय सम्माननीय भारत के उस समय तत्कालीन मुखिया अटल बिहारी वाजपेयजी जिनकी यह सोच थी कि हजार से अधिक की आबादीवाले गांव को मुख्य सड़क से जोड़ना लेकिन बीच में जब वह सरकार बदल गयी तो फिर भारत में जो दूसरी यू०पी०ए० की सरकार आयी और उसने जो नीतियां बनायीं निर्णय लिये उसके मुताबिक इन योजनाओं को बंद करके शायद पैसे को दूसरे क्षेत्र में लगाना शुरू किया और इधर कुछ समय में हमलोग सुने हैं कुछ समय पहले कि भारत की सरकार ने पुनः उस योजना में पैसा दिया है लेकिन बिहार की सरकार का धन्यवाद है और इस ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री का धन्यवाद है जिसमें वह बढ़े हुए लागत के पैसे को बिहार के ग्रामीण विकास विभाग से देना चाह रहा है ।

बंधुओ, महोदय, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जो ग्रामीण कार्य विभाग संचालित कराती है आज मुख्यमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री पुल पुलिया योजना जिसके माध्यम से बिहार के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण इलाकों में सुदूर देहाती इलाकों में सड़कें बन रही हैं और ऐसे ऐसे पुल ऐसे ऐसे विश्वास के सेतु बन रहे हैं जो एक छोटा ५-७-१० लाख रुपये की योजना के अभाव में ५-७-१० लाख रुपये जिस पुल में लागत लगना था और वह काम नहीं होता था, उसके अभाव में ६ ६ महीना तक दो तरफ से जुड़नेवाली सड़क बंद रहती थी । बरसात का समय आता था सड़क जहां पुलिया के अभाव में पुल के अभाव में टूट जाते थे पानी लग जाता था और इस प्रकार का कटाव होता था कि १०-२०-२५-५० लाख रुपया के पुलिया पुल के अभाव में ६ ६ महीने वह सड़क बंद रहती थी । आज वह स्थिति नहीं है, आज पुल पुलिया के मामले में बिहार की सरकार के द्वारा बनाये गये विश्वास के सेतु के माध्यम से आज एक गांव से दूसरा गांव जुड़ा, आज एक पंचायत से दूसरा पंचायत जुड़ा, एक ब्लॉक से दूसरा ब्लॉक जुड़ा, एक जिले से दूसरा जिला जुड़ा और खास कर पुल पुलिया और सड़क के क्षेत्र में ग्रामीण कार्य विभाग के माध्यम से काफी प्रगति हुई ।

महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति के लिये विशेष अंगीभूत योजना का प्रस्ताव किया गया और २०१० तक कुल ४२.६२ करोड़ व्यय करते हुए १०९.६९ हजार किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया गया । जिस अछूत को तब की सरकार अछूत

मानती थी, दलित मानती थी, अति पिछड़ा मानती थी और वहां से उनको निकलने का रास्ता नहीं, सड़क जाने का कोई रास्ता नहीं, बरसात के महीने जब आते थे, हमलोग छोटे थे, देखते थे अपने गांव के बगल के गांव में जहां गरीब की बस्तियां हैं, हमलोग की बस्ती भी गरीब की बस्ती है, जब बरसात का समय आता था लोग वहां से खटिया पर अपने मरीज को लादकर एक गांव से दूसरे गांव और शहर में इलाज के लिये ले जाते थे लेकिन आज वह स्थिति नहीं है । आज वह स्थिति बदली हुई है । आज वह गरीब की बस्ती भी, अनुसूचित जाति की बस्ती भी अनुसूचित जाति विशेष अंगीभूत योजना के माध्यम से जुड़ा है । महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि सीमा क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत सीमाओं पर चूंकि हमलोगों का जो जिला है पूर्वी चम्पारण जिला और उसी के बगल के, उसी जिला के विधान सभा क्षेत्र केसरिया से मैं आता हूं, पूर्वी चम्पारण जिला का जो सीमा क्षेत्र है वह नेपाल से सटा हुआ है और जब कभी हमलोग बचपन में सीमा क्षेत्र की तरफ जाते थे तो वहां के उबड़ खाबड़ रास्ते और वहां की स्थिति को देखकर सोचते थे कि बिहार की सरकार कब स्थिति को परिवर्तित करेगी और कब परिवर्तन के बाद यह सड़क अच्छी बनकर खड़ी होगी ।

...क्रमशः ...

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, क्रमशः- और इसपर हमलोग चलेंगे। सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले जो लोग हैं, जिनकी स्थिति काफी खराब है, वे लोग चलेंगे, सीमाक्षेत्र की सड़कों में भी काफी सुधार हुआ है महोदय।

अध्यक्ष:- अब आप स्थान ग्रहण करें।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह:- जी।

अध्यक्ष:- बैठिये। स्थान ग्रहण करें। आपका समय समाप्त हुआ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह:- दो मिनट में समाप्त करता हूँ। महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो क्षेत्र है वह केसरिया विधान सभा क्षेत्र, वह निश्चित रूप से विकास के मामले में अधूरा है। मैं कहना चाहता हूँ महोदय कि सरकार के जो मंत्रिगण हैं, ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग या पंचायती राज विभाग, यह सभी विभाग ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ विभाग है और इन क्षेत्रों में हमारा केसरिया क्षेत्र की भी विकास की आवश्यकता है। आज के दिन में दुनिया का सबसे बड़ा ऐतिहासिक और सबसे बड़ा और सबसे ऊँचा बौद्ध स्तूप होने के चलते वह दुनिया के पर्यटन के दृष्टिकोण से भी सबसे अच्छा और सबसे बड़ा जगह माना जा रहा है। ऐसे क्षेत्र का विकास सरकार कर रही है लेकिन एक बार पुनः मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में बैठे हुए हैं कि केसरिया क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए उसको पर्यटन के रूप में आगे बढ़ाते हुए हमारे यहाँ एक सत्तरघाट का एक पुल है, उस पुल के निर्माण कराने की विशेष कृपा करेंगे और इस निवेदन के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ और अपने दो शब्द अपने विपक्ष के साथियों के लिए, चूंकि मैं बहुत कुछ बोला नहीं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि:

"यह जमीं बदलेगा, यह आसमान बदलेगा,

और हमारे विपक्ष के साथियों को पता नहीं कि जो इतना अच्छा यह बिहार बदलेगा"

अध्यक्ष:- माननीय सदस्य डा० इजहार अहमद।

डा० इजहार अहमद:- सदरे मोहतरम और मौजू मेम्बरान आज कटौती प्रस्ताव जो विपक्ष के जरिये आये है, मैं उनके विरोध में और सरकार के बजट के मांग संख्या ३७ के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सदरे मोहतरम, आज जिस तरह से कटौती प्रस्ताव माननीय सदस्य सम्राट चौधरी जी लाये है और अपनी बात को कहने के लिए वयोवृद्ध बुजुर्ग नेता रमण जी को दिये, हमें ऐसा लग रहा था कि उनके भाषण को प्रतिपक्ष के नेता अब्दुल बारी सिद्दिकी साहब तैयार किये हैं और वही बात को वे बेचारे बोल रहे थे। खैर आवाज मेरी साथ नहीं दे रही है लेकिन सद्र महोतरम, मैं आपका सहयोग चाहता हूँ कि आज जो बिहार की हालत है, बिहार की जो सूरत है, जब पाँच साल पहले माननीय नीतीश कुमार जी ने सत्ता संभाला तो उनके सर पर काँटो का ताज था और सड़क नहीं बल्कि सिर्फ गड्डे ही गड्डे थे, कहते हैं कि "तीरे नजर देखेगे, जख्म जिगर देखेंगे,

आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे"। फर्क यह है कि आज माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार ने समुन्दर में रास्ते बनाये हैं और उस वक्त यही था कि रास्ते में समुन्दर बना हुआ था। माननीय मेरी उम्र नहीं।

क्रमशः

डा०ईजहार अहमद (क्रमशः) और मैं उस लायक भी नहीं कि मैं किसी बड़े नेता पर ऊंगली उठाऊँ । लेकिन इतना जरूर था कि आर०जे०डी० के उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद जी थे और पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि सड़कों को मैं हेमा मालिनी की गाल की तरह बना दूंगा । लेकिन उनकी सड़क पर कम और हेमा मालिनी की गाल पर ज्यादा नजर थी । इसलिए बिहार के सड़कों का यह हाल था ।

सदरे मोहतरम, ये कौन जा रहा था मेरा गांव छोड़ कर,
ये कौन जा रहा था मेरा गांव छोड़ कर,
आंखों ने रख दिये थे समंदर निचोड़ कर ।
ये कौन जा रहा था मेरा गांव छोड़ कर,
आंखों ने रख दिये थे समंदर निचोड़ कर,
मेरी आंख को तरसती रही, देखने को रात-दिन,
कभी आईना तोड़ कर, तो कभी आईना जोड़ कर ।
हम ने दीये बनाये थे, सूरज को तोड़ कर,
कभी सूरज मैंने बनाये थे, दीये को जोड़ कर ॥

सदरे मोहतरम । जिस तरह से इस सरकार ने अपने कार्य-कलाप किये, माननीय नीतीश कुमार में यह खूबी थी कि जो वे कहते थे, सो करते थे और जो करते हैं वह कहते हैं । पांच सालों के अंदर जो कार्य रहे, वे सराहनीय हैं और देश दुनियां में लोग जानने लगे । देश के बड़े नेता वित्तमंत्री श्री प्रणव मुखर्जी जी जैसे महान नेता कहने लगे कि जय बिहार, जय नीतीश कुमार । पिछले दिनों कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक मीटिंग में मैं वहां था, मीटिंग में श्री रजत शर्मा, टी०वी० के चेयरमैन वहां आये थे। वह अपने भाषण के दौरान उन्होंने बताया कि मैं हवाई जहाज से जा रहा था और दिल्ली की माननीया मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी उसी हवाई जहाज में थी और उन्होंने बताया कि बिहार के लिये श्री नीतीश कुमार जी ने इस तरह से काम किये, जिस से देश को दिशा मिला है, सीखने को मिला है और श्री नीतीश कुमार आज देश की पुकार हैं और आज देश में श्री नीतीश कुमार जैसे नेता की जरूरत है, यह श्रीमती शीला दीक्षित जैसे मुख्यमंत्री ने कहा । महोदय, ५ सालों में क्या सड़क बना, कितनी सड़कें बनी, यह सारे लोगों को पता है । आज के दिन में १७.२ कि०मी० ग्रामीण सड़कों, मुख्यमंत्री सड़कों का निर्माण हो रहा है । अध्यक्ष महोदय, बिहार में लगभग १ लाख ५ हजार किलो मीटर सड़कें हैं । अध्यक्ष महोदय, ८८,००० किलोमीटर ग्रामीण सड़कें हैं । अध्यक्ष महोदय, ५ सालों में ८६५८.४२ करोड़ खर्च कर के १७४१३ कि०मी० पूरा किया गया है । अध्यक्ष महोदय, भारत निर्माण योजना तहत २१,५०० कि०मी० है, राज्य योजना के तहत ३००० कि०मी० सड़कें प्रगति पर हैं । जिस तरह से बिहार में माननीय श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम हो रहे हैं, वह देश और दुनियां के लिये एक मिसाल बन कर के रह गया है । लगभग ३८००० कि०मी० सड़कों का निर्माण करवाना है । १६,५०० कि०मी० सड़कें प्रधानमंत्री योजना के तहत चयन में पड़ी हुई है, २१५०० कि०मी० सड़कों का निर्माण शेष रह जाता है । अध्यक्ष महोदय, सेंट्रल की जो एजेंसियां हैं सी०डब्ल्यू०डी, बी०सी०बी० जो भी हो ये सारे मिल कर बिहार को परेशान करने में लगी हुई हैं । केन्द्र समय पर पैसा नहीं दे पाता, जिस के कारण गरीबों के गांवों की सड़कें भी अधूरी रह जाती है । अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि पहले जिस तरह से बिहार के सड़कों की जो दुर्दशा थी, आज वे आईने की तरह चमक रही हैं ।

क्रमशः

डॉ० इजहार अहमद(कमशः) अध्यक्ष महोदय, मैं बतला देता हूँ, पहले कागजों पर काम होते थे लेकिन आज कम से कम नीतीश कुमार जी के राज में जमीनों पर कार्य उतर रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं सुझाव देना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी को, वो भी यहां मौजूद हैं, दरभंगा जिला में जो फरवरी, 2009 में जो सूची बनी थी मुख्यमंत्री ग्राम योजना की उसका क्रियान्वयन काफी स्लो है उसमें और प्रगति लाने की जरूरत है, इसी तरह से हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इजहार साहब जिला की जो बैठकें हुई हैं फरवरी, 2009 में, सारा काम उसमें लंबित पड़ा हुआ है माननीय मंत्री जी आप यहां मौजूद हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बतलाना चाहता हूँ जिस तरह से विशनपुर चौक की सड़कें थीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि विपक्ष को भी सहयोग करना चाहिए आपको, माननीय सिद्धिकी साहब का क्षेत्र है, उनकी समस्या को भी हमें ही उठाना पड़ता है, धनश्यामपुर से यजोपट्टी तक की सड़कें हैं, उसकी जर्जर हालत है और पटनियां से जगन्नाथपुर की सड़कें जो जर्जर हैं उस पर आवागमन बिल्कुल ठप्प पड़ा हुआ है, उसे बनाना अति आवश्यक है, दरभंगा जिला के हाट गाछी से लेकर के सुपौल तक का रास्ता है वह जर्जर है, आवागमन बिल्कुल ठप्प पड़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उन सड़कों को बनाना अति आवश्यक है, इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे जो समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ।

मेरे जमाने को मुझसे बड़ी शिकायत है,
इसीलिए तो मुझे सच बोलने की आदत है,
सच्चाई के आग के सामने,
जोर भला कब चलता है,
एक जरा सच बोल दिया था,
आज तल्लू मुंह जलता है।

श्री राणा गंगेश्वरः अध्यक्ष महोदय, मंत्रीगण, बरिष्ठ साथी आज हम ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रस्तुत डिमांड..

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आज ग्रामीण कार्य विभाग के डिमांड पर चर्चा चल रही है।

श्री राणा गंगेश्वर : तो ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा प्रस्तुत आय-व्यय बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ तथा कटौती प्रस्ताव के विरोध में भी बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार पर हफ्तों को गौरव प्राप्त है कि माननीय नीतीश कुमार जी जैसे कुशल नेता इस राज्य को मिले हैं जिसके कारण बिहार में, न केवल प्रदेश में, बल्कि देश और दुनिया में अपना स्थान बनाने लगा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब पिछले दिनों हम बिहार के विभिन्न जिलों में किसानों के सवाल पर रथ यात्रा करते थे तो लगता था कि एक डेग चलना मुश्किल है, इतनी सड़कें टूटी हुई थीं कि हम सोचते थे कि कौन महापुरुष पैदा होगा जो एक साथ बिहार के इन टूटे हुए सड़कों को बनाने का काम करेगा लेकिन बेहद खुशी हुई कि माननीय नीतीश जी, मोदी जी के अगुआई में आज बिहार की तमाम सड़कों का उद्धार हो गया है

जहां गाड़ी चलती नहीं थी, अगर ब्रेक लगा दिया जाता है तो 10-20 मीटर तो ऐसे ही छहल जाता है ऐसा रोड बन गया है।

(इस अवसर पर सभापति, श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने आसन ग्रहण किया)

माननीय सभापति महोदय, अभी 16 अरब से अधिक बजट का प्रावधान किया गया है जिसमें केवल 12 अरब योजना मद में खर्च है। वर्ष 2009 तक 4742 कि०मी० सड़कों का मरम्मत हुआ है जो एक ऐतिहासिक काम हुआ है। माननीय नीतीश कुमार जी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भूतल परिवहन मंत्री बने थे (कमशः)

श्री राणा गंगेश्वर: कमश: और 5824कि०मी०की मरम्मत हुई है । ऐतिहासिक काम हुआ है । माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के पहले अटल जी की सरकार में कुछ दिनों पहले भूतल परिवहन मंत्री बने थे । उस जमाने में वर्षों से बिहार में कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं हो रहा था लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने अपनी बुद्धि और प्रभाव क्षमता से 28एन०एच० उस समय बनाने का काम किया जिससे बिहार को एक नई सुविधा मिली और आज जिस तरह से सड़कों का विकास हो रहा है और अगली बार पांच साल के लिए बजट का प्रावधान किया गया है अब हमको विपक्ष के नेताओं से आकर खोजना पड़ेगा, कौन सड़क गली बच रहा है आप ही बताइये, उसका निर्माण कराएंगी । ऐसा कार्य इस सरकार द्वारा चलाया जा रहा है । माननीय नीतीश कुमार जी स्वयं इंजीनियर हैं और एक अच्छे इंजीनियर को तलाश कर कार्य विभाग उन्होंने सौंपा है और लगता है कि ये कुशल इंजीनियर हमारे भाई भीम सिंह जी भी इस विभाग को और गुणात्मक गति देंगे और बिहार को एक नई दिशा मिलेगी । जो ऐतिहासिक काम उन्होंने किया है वह एक-से-एक महत्वपूर्ण है जिसकी जितनी भी चर्चा की जाए, कम है । लेकिन एक छोटी बात हम रखना चाहेंगे जो मेरे अनुभव से बहुत ऊँची बात है । माननीय मुख्यमंत्री जी की दृष्टि वहां गयी । आज बड़े-बड़े नेताओं का, अधिकारियों का राजकीय सम्मान से अन्त्येष्टि होती है लेकिन पहली बार है जब गरीबों को सरकारी अन्त्येष्टि के लिए पंद्रह सौ रूपया अन्त्येष्टि योजना में दिया गया । यह ऐतिहासिक फैसला है ..थपथपी.. यह मुख्यमंत्री के सोच का एक परिणाम है कि एक साधारण आदमी के उपर उनकी दृष्टि गई जिसको कफन नहीं हो रहा था, जलावन का उपाय नहीं था, मरने के बाद कर्जा खोजना पड़ता था, ऐसे लोगों को पंद्रह सौ रूपया देकर गरीब-गुरूवा का राजकीय सम्मान के साथ दाह-संस्कार किया गया, यह ऐतिहासिक बात है ।

महोदय, हम कहना चाहेंगे कि जिस तरह से चौतरफा पंचायतों में आज विभिन्न प्रकार के आरक्षण दिए गए, हर पांच साल में चुनाव हो रहे हैं । कहीं कोई बाधा नहीं है । इस प्रकार का माहौल देखा नहीं गया था । अठारह वर्ष के बाद बिहार का पंचायत हुआ । लोग तर्क देते थे, सरकार के मुख्यमंत्री मंत्री तर्क देते थे कि पंचायत के चुनाव में घोर खून-खराबा होगा, इसलिए होना ही नहीं है । लेकिन आज यह सरकार चुटकी बजा कर चुनाव-पर-चुनाव कराये जा रही है, और जो बूथ कैप्चरिंग का सिलसिला चलता था, हमलोग सोचते थे कि बूथ कैप्चरिंग कैसे बंद होगा, आज किस तरह से उसमें गिरावट और कमी आई है, आम जनता गरीब-गुरूवा मुश्तैद होकर वोट देने का काम किया है, वह इस सरकार की सफलता और सफल प्रयास का ही देन है । हम आपसे कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्रीजी ने, पूरे देश में पहला बिहार राज्य है जहां कृषि कैबिनेट बनाने का काम किए हैं । तो जो भी ये काम कर रहे हैं, प्रदेश और देश के अगुआई का काम करते जा रहे हैं लेकिन कृषि के क्षेत्र में कृषि कैबिनेट बनाने का काम किया गया है । चूंकि गांव के किसान, सड़क उनको जरूरी है, उनके फसल मार्केट में कैसे आएंगे, किस तरह से आसानी से बड़े-बड़े शहरों में उनके कृषि उपज को पहुंचाया जाएगा, लाभकारी मूल्य मिलेगा, इसलिए आज सड़क गांव के लिए बहुत आवश्यक हो गया है और इसी संदर्भ में

हम निवेदन करना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा सरकार से कि कृषि कैबिनेट में ग्रामीण कार्य विभाग को भी रखा जाए। हमारा क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ था, हमारे जो बीस वर्ष से वहां विधायक थे माननीय राजद के विधायक हुआ करते थे जिनको काम से कोई लेना देना नहीं है और सबसे बड़ा गांव, हमारे इलाका का पांच पंचायत का एक गांव धमन जहां हमारे लालु जी राबड़ी जी बार-बार माथा टेकने, खोइछा मांगने जाते थे, हमारे वहां के विधायक एक इंच अपने घर का रोड नहीं बनवा सके और इतना बड़ा गांव सड़क से उपेक्षित रह गया। जब उनका स्वयं गांव उपेक्षित रह गया, पूरा इलाका उपेक्षित रह गया है। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे इलाके में बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं, मुख्य सड़कें हैं, जो ब्लॉक अनुमंडल को जोड़ता है, अछूता है, उसको बनवाने में सहयोग दिया जाए। हमारे क्षेत्र को बाया नदी दो भागों में बांटता है और उसमें सबसे बड़ी समस्या पुल की होती है। पांच साल में या तो हमारे वहां के लोगों ने प्रयास नहीं किया। एक भी पुल निगम के द्वारा हमारे विधान सभा में नहीं बन सका। अभी 13 जनवरी को मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत सेतु का चयन कर अनुश्रवण समिति की बैठक प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में वहां तय हुआ और हुआ कि सबसे कम हमारे यहां हुआ है इसलिए एक नम्बर हेमंतपुर घाट, मड़वा घाट.....कमशः

श्री राणा गंगेश्वर : ..क्रमशः... और मरवा घाट, थनुआ घाट, नारायणपुर अदलपुर घाट, नारायणपुर बस्ती घाट और सिवरा अदलपुर घाट, ये छः जगह जिसमें छोटा भी पुल बन सकता है लेकिन हेमंतपुर अमरवा में बड़ा पुल बनने की जरूरत है । यह काम हम चाहेंगे कि हमारी सरकार की ओर से गरीब जनता, उपेक्षित जनता के लिए काम किया जाय ।

एक निवेदन और हम करना चाहते हैं कि जिस तरह से ग्रामीण सड़कों का विकास हो रहा है, चौतरफा विकास हो रहा है, उसमें महासेतु की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा काबिले तारीफ है । किसी ने माँग नहीं किया था पटोरी-बख्तियारपुर के बीच गंगा पर महासेतु बनाने का, वह काम उन्होंने करके एक ऐतिहासिक फैसला किया है । उस इलाके को, समस्तीपुर, वैशाली और मिथिलांचल के इलाके को, उधर झारखंड के इलाके को सीधा जोड़ने का ऐतिहासिक काम किया गया है । हम उसमें एक और आग्रह करना चाहेंगे कि उस पुल के उत्तरी छोर को पटोरी-ताजपुर तक फोर-लेन बनाया गया है लेकिन जिस तरह गाँधी सेतु की हालत जर्जर है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में पटोरी-बख्तियारपुर सड़क-पुल ही लोगों के मुख्य आवागमन का केन्द्र बन जाय । इसलिये हम एक निवेदन करेंगे कि जदुआ-हाजीपुर से लेकर महनार-बछवाड़ा को भी फोर-लेन में जोड़ा जाय ताकि जो गाड़ियों का दबाव हो, आसानी से द्रुत गति से उनको गंतव्य तक पहुंचाया जा सके । साथ-ही-साथ हम एक और आग्रह करना चाहेंगे कि जो बीच का दियारा है, चाहे वह राघोपुर दियारा हो या रामनगर दियारा हो, ऐसे पचीसों गाँव हैं जो दो गंगा की धारा के बीच में रहते हैं, जब इतना बड़ा सेतु बन रहा है, उस पुल पर से केवल ढाल उतारने का काम कर दिया जाय दियारे पर तो २०-२५ गाँव को दोनों तरफ से पुल का सुविधा प्रदान हो जायेगा और बिना खर्च में ढाल उतारने से यह लाखों आबादी को पुल की सुविधा मिल जायेगी । फिर नदी के उत्तरी किनारा के बाद...

श्री सभापति (श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह) : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें ।

श्री राणा गंगेश्वर : वह सड़क उतरती है उसमें भी एक ढाल उतारने का प्रयास किया जाय ताकि जितना बड़ा सपना माननीय नीतीश कुमार जी ने देखा है और अमल कराने जा रहे हैं, इसके लिए पूरे इलाके के लोग आज उनपर खुश हैं, गौरवान्वित हैं और आभार व्यक्त करते हैं लेकिन उसमें ढाल उतारने का भी काम हो । इन्हीं शब्दों के साथ, हमें बोलने के लिये जो समय दिया, उसके लिये आभार व्यक्त करता हूँ ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : माननीय सभापति जी, मैं ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ । हमलोग तो इस सदन के प्रथम बार सदस्य हुये हैं और ऐसे समय में सदस्य हुये जब सत्ता पक्ष की आंधी चल रही थी, विपक्ष की भी कड़ी घेराबंदी थी लेकिन वर्ष २००० में जब मैंने एक मार्शल गाड़ी खरीदी थी, २००५ में जब उस गाड़ी को बेचने की बात आई तो २००५ में ५ वर्षों में जितना गाड़ी का दाम था, उससे ज्यादा उसके मेन्टेनेंस में खर्च हो गया था । बिहार के सड़कों की हाल इतनी बुरी थी कि गाड़ी के दाम से ज्यादा रूपया गाड़ी के मेन्टेनेंस में

खर्च हो गया । २००६ में जब दूसरी गाड़ी लिया उस गाड़ी को बेचकर तो २००६ से २०११ है अभी ५ साल में गाड़ी के दाम का २५-३० प्रतिशत राशि गाड़ी के रख-रखाव पर मात्र खर्च हुआ, यह कोई पवन जायसवाल के अकेले गाड़ी के मेन्टेनेंस की बात नहीं है, बिहार की तमाम आम जनता जो लोग गाड़ी की सुख-सुविधा उठाते हैं, चाहे जो लोग भाड़ा की गाड़ी की सुविधा लेते हैं, उनकी गाड़ियों का यह हाल है । बिहार में जो सड़कों की व्यवस्था सुधरी है, जो हालात सुधरी है, यह छुपी हुई बात नहीं है । बिहार में बदलाव तो भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में हुआ है लेकिन विधि व्यवस्था और सड़क के क्षेत्र में बिहार में पाँच वर्षों में जो सफलता हासिल किया गया है, वह काबिले तारीफ है । मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ - ढाका और घोड़ासाहन से, मोतिहारी से ढाका होते हुये फुलवरिया जाने के लिए हमलोगों को सप्ताह में सोचना पड़ता था कि कब जायें, प्रोग्राम बनाकर टाल देना पड़ता था, इतनी बुरी हालत थी सड़क की । लोग जब यात्रा करते थे तो हनुमान चालीसा का पाठ करते थे कि कहीं गड़ढ़े में गाड़ी न पलट जाय, जान जोखिम में न पड़ जाय, इसके लिये हनुमान चालीसा का पाठ करते थे । लेकिन आज सड़कों की स्थिति ऐसी है कि पलक झपकता है तो आदमी १०-१५ किलोमीटर की यात्रा तय कर लेता है, बिहार सरकार का सड़क के क्षेत्र में सकारात्मक काम हुआ है लेकिन कुछ क्षेत्रों में जो कार्यपालक अभियंता हैं, कनीय अभियंता हैं, सहायक अभियंता हैं, इनकी मनमानी भी छुपी हुई नहीं है । ऊपर तो नीति अच्छी बनी, काम अच्छे हो रहे हैं लेकिन कार्यों की गुणवत्ता, कार्यों में कमीशन का जो बाजार है, इसमें कहीं कमी आने का काम नहीं हुआ है, मैं कहना चाहता हूँ ।

...क्रमशः...

श्री पवन कुमार जायसवाल : (क्रमशः) मैं कहना चाहता हूँ कि १५ प्रतिशत बीलो टेंडर होता है ग्रामीण कार्य विभाग में, पथ निर्माण विभाग में, भवन निर्माण विभाग में, इसमें प्रतिस्पर्धा हुआ और जो टेंडर की प्रक्रिया बनी और ठीकेदारों के बनाने के लिए जो सिस्टम बना, उससे ठीकेदारों की संख्या बढ़ी है। ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा लिये, १५ परसेंट बीलो जाने में नये-नये लोग प्रतिस्पर्धा में १५ परसेंट बीलो चले जाते हैं, इससे कार्य की गुणवत्ता में कमी आती है। पथ निर्माण विभाग ने एक साल पहले एक नीति बनाया था, मैंने उस पत्र को पढ़ा है, उसमें है कि जीरो से ऊपर और १५ प्रतिशत से नीचे, अगर बीलो चला जाता है कोई कंट्रेक्टर तो उसी के हिसाब से ३ परसेंट पर इतना अंतिम ८.७५ परसेंट एक्सट्रा उसको डिपोजिट करना है, एन०एस०सी० जमा करना है जितना बीलो चला गया, उसके हिसाब से। मैं पूर्वी चम्पारण जिले से आता हूँ, मैंने जिला के अनुश्रवण समिति की बैठक में यह मामला उठाया, मैंने ग्रामीण कार्य विभाग और पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता से पूछा कि एक साल पहले जब यह पत्र निकला सरकार के स्तर से तो क्या आपने इसको लागू किया है? जितने लोग १५ परसेंट बीलो, १० परसेंट बीलो राशि में टेंडर लेते हैं, उनका आपने मार्जिन मनी जमा कराया है तो अब इसको लागू करने जा रहे हैं। सरकार ने अगर गुणवत्ता पर, आखिर गुणवत्ता कब ठीक होगा, १५ परसेंट बीलो ठीकेदार चला जायेगा नीचे और वह १५ परसेंट कहां से पूर्ति करेगा। २० परसेंट कमीशन पदाधिकारी लेने का काम करते हैं और बदनामी जनप्रतिनिधियों के माथे पर चली जाती है। अब कहने की जरूरत है कि जितना अच्छा काम करने का प्रयास राज्य सरकार कर रही है, उसको धरातल पर उतराने में नीचे के स्तर के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूमिका जब तक नहीं सुधरेगी, तमाम विभागों में साकारात्मक सुधार नहीं हो सकता है महोदय। ये १५ परसेंट बीलो का पत्र एक साल पहले निकला, अगर इसको विभाग के पदाधिकारियों ने जमीन पर नहीं उतारा तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री महोदय, विभाग के जो सक्षम पदाधिकारी हैं, वैसे कार्यपालक अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रस्ताव रखेंगे, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे। सरकार का इतना महत्वपूर्ण पत्र क्यों नहीं लागू हो पाया, इसलिए महोदय, बड़े-बड़े माननीय सदस्य हैं जानकारी के मामले में, हमलोग को तो सिखना है प्रथम बार आये हैं, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री जनक सिंह : माननीय सभापति महोदय, आज वित्तीय वर्ष २०११-१२ में ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जो आय-व्यय का प्रस्ताव लाया गया है, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय सभापति महोदय, सदन में सत्ता पक्ष के द्वारा यानी हम सबों के द्वारा जो जनादेश का आवाज उठा, जो जन-जन तक पहुंचा ही बिहार के धरती पर, साथ ही पूरे बिहार में, पूरे देश में इसकी गुँज उठी और हमारे विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता मान्यवर सिद्धिकी साहेब अभी नहीं है, बाहर गये हैं और वे इस जनादेश को देखकर

घबरा उठे कि कौन सी बात, कौन सी राज कि इतने कम समय में यानी ५ वर्षों में इतना बड़ा जनादेश प्राप्त हुआ । काश प्रतिपक्ष के नेता एवं इनके मित्रगण पढ़ा होता कुराण को, पढ़ा होता बाईबिल को, पढ़ा होता गीता और रामायण को, अगर अध्ययन किये रहते तो इनके मन में यह भाव उत्पन्न नहीं होता क्योंकि तुलसी जी ने अपने रामायण में बाल्य काण्ड के अन्दर लिखा है -

"गुरु गृह गये पढ़न रघुराई
अन्त काल विद्या सब आई । "

यानी बहुत कम समय में प्रभु राम ने सारे ज्ञान अर्जित किये थे और यहां तो हमको ५ वर्षों का समय मिला । हम इससे खुश नहीं है मान्यवर,

..... क्रमशः

लेकिन नाटकीय खेल से हमें हराया गया, लेकिन हमने भी प्रतिज्ञा की थी कि आयेगे। बरसो तो झूमकर, खुदा न खास्ते किसी न किसी कारण से २००५ में जीते तो लेकिन मैं यहां नहीं आ सका। प्रारंभ में जब राम का राजतिलक हो रहा था तो माताश्री ने १४ वर्ष के लिए उन्हें वनवास भेज दिया। वही बात हुई, भाई हम तो जीत गये और आज हम पूरे जनादेश के साथ आये हैं और हमें कुछ करना है और यह विभाग जहां तक गांव गलियारे खेत खलिहान विद्यालय महाविद्यालय की बात है, आजादी के बाद अब देखिये जहां पहले मुख्य सड़कें ही हुआ करती थीं, लेकिन जब केन्द्र में एन०डी०ए० की सरकार बनी तो हमारी पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की और हमारे ही नेता इस सदन के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना दी। किसी ने किया और किया तो हमने किया। आप तो मैं मैं मैं लगे हैं, हम हम में रहे। आपकी कौरवों की भूमिका रही और हम पाण्डवों की भूमिका में रहे। महाभारत के अंदर जो खेल हुआ मैं और हम पाण्डवों के अंदर पांच भाई थे, मिलजुलकर रहा करते थे और कौरवों के अंदर अनेकों थे, मिलजुलकर रहा नहीं करते थे, इसलिए महाभारत जो हुआ उसमें पाण्डव में पांच थे और कौरवों में अनेक लोग थे, पाण्डव में कौरव में जीत पाण्डवों की हुई। इसलिए मैंने नहीं आप थे जो अपने लिये श्रीमती के लिए संबंधी के लिये काम किये, लेकिन बीच राह में ही संबंधी आपको छोड़कर चला गया, आपको जनादेश था, आप क्यों नहीं आये। हम पिछले पांच वर्षों से आगे बढ़ते जा रहे हैं, गांव गलियारे, खेत खलिहान, विद्यालय महाविद्यालय के बीच योजनाएं चल रही हैं और उसमें रहनेवाले सारे लोग खुशहाल हैं। अभी हुआ है क्या, याद है गांव गलियारे में रहनेवाले के बीच एक समस्या उत्पन्न हो गयी थी, अब बाहर से डाक्टर लाना है, विकास के लिए इंजीनियर लाना है, क्या किसी ने उसपर सोचा लेकिन आज हमारे अभी अभी मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के मध्यम से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से आज वहां पहुंच रहे हैं। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि आनेवाला दिन हमारा है चूंकि हम समाज के लिए जी रहे हैं, मर रहे हैं और आप भाई के लिए, श्रीमती के लिए, साला के लिए काम किये। अब मैं विधायक मद की जो योजना पहले थी और जो उसको हटाया गया है बहुत ही उचित हुआ है इसलिए कि हमारे क्षेत्र में.....क्रमशः

श्री जनक सिंह : ...क्रमशः ...

इसलिये कि हमारे क्षेत्र, बिहार के अंदर मात्र तरैया विधान सभा क्षेत्र के अंदर वहां के आप ही के प्रतिपक्ष के, आज वो नहीं हैं, विधायक रहा करते थे और उन १५ वर्षों की योजनाओं को हम मंगा लें और हम देख लें उन योजनाओं को, एक ही योजना को बारम्बार किया गया है, पैसे का दुरुपयोग किया गया है और एक विभाग का एक जूनियर इंजीनियर द्वारा ..

सभापति (श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह) : अब समाप्त करें । माननीय सदस्य, श्री संतोष कुमार निराला ।

श्री जनक सिंह : माननीय, एक क्षेत्र की समस्या है । उस समस्या को रखकर अपनी वाणी को विराम देता हूं ।

सभापति (श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह) : जनक बाबू आप बैठ जाइये । हो गया । हो गया आपका । अगर लिख कर लाये हैं तो सामने दे दीजिये रिपोर्टर के यहां भेज दीजिये । आप बोलिये निरालाजी ।

श्री संतोष कुमार निराला : माननीय सभापति महोदयजी..

सभापति (श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह) : आप बोलिये । माननीय सदस्यों की भावना की खातिर करें ।

श्री संतोष कुमार निराला : माननीय सभापति महोदय, आज हम ग्रामीण कार्य विभाग की तरफ से २०११-१२ के जो बजट प्रस्ताव लाया गया है उसमें मैं सरकार के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

सभापति महोदय, आज बिहार की सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमारजी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और उस सरकार के तहत जो ग्रामीण कार्य विभाग ने इस सूबे में ग्रामीण क्षेत्रों में जो महत्वपूर्ण योजनाओं को चिन्हित किया है, सुदूर इलाकों में योजनाओं को पूरा करने का प्रयास किया है सभापति महोदय, जैसा कि मालूम है ग्रामीण क्षेत्रों में बिहार की ८० परसेंट सामान्य जनता निवास करती है और उनके विकास के लिये उनकी समृद्धि के लिये जो सरकार ने समुचित फैसले लिये वह फैसला सराहनीय है और मैं अपनी तरफ से इस सदन के माध्यम से इस सरकार को और सरकार के मंत्री श्री भीम सिंहजी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपकी पैनी नजर सुदूर के इलाकों ग्रामीण क्षेत्रों में आपकी पैनी नजर पड़ी ।

सभापति महोदय, जैसा कि हमलोग देखते हैं एक समय था २००५ के पहले जो इस सूबे में सरकार थी और वह सरकार बहुत लम्बे समय तक अपना कार्य किया । सभापति महोदय, मैं उस इलाके से आता हूं और हमने देखा बक्सर जो एक धार्मिक स्थान है और बक्सर जिले में अनेक प्रांत के लोग प्रत्येक साल आया करते हैं और लोग देशाटन के लिये घूमने के लिये सुदूर गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जाया करते थे और हमलोगों से मिलकर यह बताया करते थे नहीं मालूम कि सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़क है, बिहार के उस समय की स्थितियां और परिस्थितियां ये थीं, हमलोग शर्म से अपने सर को नीचे गिरा लेते थे यह हालात थे उस समय २००५ के पहले की सरकार के ।

श्री संतोष निराला, क्रमशः- सभापति महोदय, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आज बिहार सरकार, एन०डी०ए० की सरकार सुशासन की सरकार, अगले कदम पर पायदान रख रही है और उसी कड़ी में आज उनकी उपलब्धियों को आज बिहार सरकार के तमाम उपलब्धियों को या वह विकास के मामले में हो, या संस्कृति के मामले में हो, गरीबों के हित में योजनाएँ लागू की गयी हैं, उसके मामले में हो, आज राष्ट्रीय स्तर पर, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर, आज उच्च श्रेणी के लोग इसको चिन्हित कर रहे हैं, उच्च श्रेणी के लोग आज इस उपलब्धियों को गिना रहे हैं, इसलिए बिहार के लोगों का सर ऊंचा उठा है और देश के पैमाने पर और राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा उठा है। सभापति महोदय, राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली बिहार के लोग जाते थे, आज उस बिहार प्रदेश का नाम इतना रौशन हुआ है कि आज हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के लोग बिहार के लोगों को गले से गले मिलाते हैं और भाईचारा के तहत ऊंचा पीढ़ा देते हैं, आज गर्व से बिहार का नाम आगे हुआ है। सभापति महोदय, आज हमारी सरकार ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, ए०डी०ए० के नेतृत्व में, जो ग्रामीण कार्य विभाग की तरफ से जो योजनाएँ लागू की हैं, उस नई दिशा में बढ़ते बिहार के भविष्य निर्माण की जो चुनौतियाँ हमारे माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है और संकल्प के साथ स्वीकार किया है कि आने वाले दिनों में बिहार आगे बढ़ेगा, इसलिए उनका सोच है और हर दिन सोच है कि:- "हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन"। सभापति महोदय, बिहार राज्य गाँवों का राज्य है और इसके समृद्धि के लिए हमारी सरकार ने बहुत सी योजनाओं को लागू किया है। मुख्यमंत्री सड़क योजना, जिनके बारे में तमाम सदस्यों ने चर्चा किये, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, एक समय था, हम लोगों ने देखा है, आज इतना बड़ा परिवर्तन हुआ कि आज हमारे मुख्यमंत्री जी, सुदुर के गाँवों में सड़कों का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है, आज अच्छे-अच्छे सड़कों का निर्माण हुआ है, आज साईकिल योजना, बच्चे और बच्चियाँ जब साईकिल पर चढ़कर अपने विद्यालय के लिए जाती हैं, तो इतने सुंदर रोड बने हुए हैं कि कम समय में ही आज साईकिल पर चढ़कर बच्चे और बच्चियाँ स्कूल पहुंच जाती हैं, यह देखने को मिलता है, बिहार का छवि बदला है और साथ ही सभापति महोदय, अगली कड़ी में "आपकी सरकार, आपके द्वार" योजना जो हमारे ग्रामीण कार्य विभाग की तरफ से लागू किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निदेश में लागू किया गया है, "आपकी सरकार आपके द्वार योजना" आज इसमें मनोबल जो सुदुर के इलाके में ग्रामीण क्षेत्र में जो आम जनता निवास करती है, उसका मनोबल बढ़ा है। आज इस सरकार से काफी उम्मीद की है, आज भाईचारा कायम हुआ है और भाईचारा के तहत तमाम बड़ी से बड़ी, जो भी समस्या आती है, ग्रामीण क्षेत्र में आम जनता बैठकर माननीय मुख्यमंत्री जी के निदेश में, माननीय मुख्यमंत्री जी के उस सोच के आधार पर, बड़े से बड़े फैसला करने के लिए बैठकर हल कर लेते हैं।

सभापति (श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह):- माननीय सदस्य अब आप समाप्त करें।

श्री संतोष निराला:- सभापति महोदय, मैं बक्सर जिला के राजपुर विधान सभा क्षेत्र से आता हूँ और पहली बार आपकी अनुमति से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

श्री संतोष निराला (क्रमशः) महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री एवं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि राजपुर विधान क्षेत्र जो सुरक्षित क्षेत्र है, माननीय मंत्री जी, २ सड़कें हैं, जो तीन-तीन प्रखंडों को जोड़ती है, मैं लिख कर आप को दे दूंगा, आप इसे बनवाने का कष्ट करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

सभापति (श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह) : भिजवा दीजिये। श्री प्रेम रंजन पटेल।

श्री प्रेम रंजन पटेल : आदरणीय सभापति महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा जो बजट लाया गया है १६,३४,५०,३७,०००/-रुपये का, उस के पक्ष में मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ और विपक्ष के द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव लाया गया है, मैं उस के विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ।

सभापति महोदय, विपक्ष के कई माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया और इस चर्चा में हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यगण सरकार की केवल खामियों और अवगुणों को दर्शाने का काम कर रहे थे। मैं उन की बातों को गौर से सुन रहा था। लेकिन इन की संख्या को देख कर मुझे यह कहना पड़ रहा है कि

"आज विरान उनका घर देखा,
तो कई बार झांक कर देखा,
पांव टूटे हुये नजर आये,
एक ठहरा हुआ सफर देखा।

महोदय, इन को १५ वर्षों तक समय मिला था, १५ वर्षों तक इस बिहार की सत्ता पर ये काबिज थे और १५ वर्षों में बिहार की हालत क्या थी? पूरा बिहार जंगल राज में तबदील हो गया था। चारो तरफ पूरे देश के अंदर चर्चायें होती थी और जब बिहार में जंगल राज की चर्चा होती थी, सभापति महोदय, मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूँ, प्रतिनिधित्व करता हूँ, अगर उस विधान सभा का नाम लिये उस जंगल राज की चर्चा अधूरा रहता था। लेकिन आज परिवर्तन हुआ है। कहीं सड़कें नहीं थी, किसी गांव में सड़कें नहीं थी, आजादी के आज ६३-६४ साल बीत गये, इतने दिनों के अंदर में गांवों में सड़क नहीं जाती थी। लेकिन आज ५ वर्षों के अंदर जो सड़क की स्थिति है, जब आप पूरे देश के अंदर की स्थिति का आकलन करेंगे तो देखेंगे, उस में अभी हमारे बिहार में, सड़कों की कमी है। लेकिन ५ वर्षों में बहुत सारे सड़कों के निर्माण हुये हैं। जब आप प्रति लाख की आबादी पर आकलन करेंगे, पूरे देश का, जो औसत है सड़क का, उस का २५७कि०मी० है और हमारे बिहार में प्रति लाख केवल ९०किमी सड़कें हैं। वहीं अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे, तो १००वर्ग कि०मी० पर सड़कों की लंबाई पूरे देश के अंदर जो औसत है, वह ७५कि०मी० है और हमारे बिहार में ५१ कि०मी० है। सड़कों के क्षेत्र में हम अभी भी बहुत पीछे हैं। लेकिन ५ वर्षों के अंदर जिस प्रकार से हमारे सरकार ने सड़कों के क्षेत्र में काम किया है, आज उसे सराहने लायक है, देखने लायक है। महोदय, २०१० तक आज पूरे बिहार के

अंदर ९०,००० कि०मी० सड़कें हो गयी है और ९०,००० कि०मी० सड़कें इस राज्य के अंदर है, उन में तीन चौथाई भाग ग्रामीण सड़कें हैं, जो गांवों को जोड़नेवाली सड़कें हैं । लेकिन आप २००५ के बाद देखेंगे कि २००५ से सड़कों का कितना निर्माण का काम हुआ है । औसत आप देखेंगे, ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत सभापति महोदय, २००५-०६ में इस विभाग का जो योजना व्यय था, वह मात्र ३३२.८९ करोड़ था । लेकिन आज बढ़ कर २०११-१२ के बजट में १२०० करोड़ ४० लाख रुपया योजना व्यय केवल हो गया है । आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है । कितनी बढ़ोत्तरी की गई है जिस से आज नई सड़कों का, नई योजनाओं का, नये कार्यक्रम, सड़कों के निर्माण के लिये इस के माध्यम से लिये जायेंगे । अध्यक्ष महोदय, बीते ५ वर्षों में हमारी सरकार ने दिसंबर, २०१० का केवल १८ हजार ४१ कि०मी० ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य पूरा करने का काम किया है ।

क्रमश :

श्री प्रेम रंजन पटेल(कमशः) राज्य अपने संसाधन से 3476.98 करोड़ रू० व्यय कर के 8225.3 कि०मी० सड़कों का निर्माण करने का काम किया है, इसके साथ ही 926.4 करोड़ रू० की लागत से 4880 कि०मी० सड़कों के पथों का मरम्मत करने का काम यह सरकार ने किया है। वर्ष 2011-12 में अगर आप आकलन करेंगे तो 16.8 कि०मी० प्रतिदिन के हिसाब से सड़कों के निर्माण का काम ग्रामीण कार्य विभाग और सरकार ने करने का काम किया है। सभापति महोदय, सड़कों के निर्माण के लिए कई प्रकार की योजनाएं हैं, इसमें मुख्य जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आप सब लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जब एन०डी०ए० की सरकार केन्द्र में थी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो उनकी दूरदर्शी नीति और उनकी सोच के कारण गांव को जोड़ने के लिए यह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारम्भ किया गया था। वर्ष 2000 से 2003 के बीच में प्रथम एवं द्वितीय चरण के समय इस राज्य को 650 करोड़ रू० उपलब्ध करायी गयी थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माण के लिए लेकिन उसके तहत जो काम होना चाहिए था जो उपलब्धि होना चाहिए थी वह उस समय की तत्कालीन सरकार ने प्राप्त नहीं कर सकी, जिसके कारण हमारा जो लक्ष्य था सड़कों के निर्माण के लिए वह नहीं मिल सका, भारत सरकार, केन्द्र सरकार ने उस राशि को रोक दी इसलिए कि उसका जो यूयटिलाइजेशन है जो खर्च का हिसाब है, सड़कों के निर्माण का काम जिस गति से होना चाहिए था वह नहीं हो सका, यूटिलाइजेशन नहीं भेजा जा सका इसलिए केन्द्र सरकार ने यह तय किया कि हम केन्द्रीय एजेंसियों के माध्यम से सड़कों का निर्माण करेंगे। पांच केन्द्रीय एजेंसी उस समय का एन०बी०सी०सी०, एन०पी०सी०सी०, एन०एच०पी०सी०, सी०पी०डी०एल० एवं इस्कॉन के माध्यम से पूरे बिहार की सड़कों के निर्माण के लिए उनके माध्यम से सड़कों के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया गया, तीन फेज से लेकर सात फेज तक सभापति महोदय उनके जिम्मे 13500 कि०मी० लम्बे सड़कों के निर्माण का कार्य सौंपा गया लेकिन वह केन्द्रीय एजेंसी भी जिस प्रकार से करना चाहिए था, जिस गति से करना चाहिए था, वह भी असफल रही है। आज वह सड़कों के निर्माण के लिए जो उनका डी०पी०आर० होता है, वह तो अधूरा रहता है, अब बढ़े हुए रेट से रिभाईज्ड नहीं कर सकते हैं, यह अधिकार उनको नहीं है, जिसके कारण आज ठीकेदार संवेदक उनके नहीं आते हैं और जिन सड़कों के निर्माण के लिए उन्होंने स्वीकृति प्रदान किया है, आज उसके भी गति नहीं है उसमें भी काम नहीं चल रहा है, बहुत सारी सड़कें अधूरे हैं, जिनकी स्वीकृति हुई है, ठीकेदार को काम देकर के और उसके बाद वह काम केन्द्रीय एजेंसिय उनके माध्यम से नहीं करा रही है इसलिए अधूरे पड़े हुए हैं, अब उसके बाद बिहार सरकार से भारत सरकार को भारत निर्माण योजना के तहत 1000 आबादी वालों गांव को पक्की सड़कों से जोड़ने हेतु सरकार ने, ग्रामीण कार्य विभाग ने यह तय किया कि हमारी जो एजेंसी है, जो ग्रामीण कार्य विभाग के अन्दर काम करने वाली एजेंसी है बिहार ग्रामीण पथ एजेंसी, हम उसके माध्यम से उसका निर्माण कराने का काम करेंगे लेकिन उसके लिए जो राशि है जो भारत सरकार को देनी चाहिए वह राशि नहीं देती है, 1400 करोड़ रू० 17000 करोड़ में से 1400 करोड़ और उसके बाद 300 करोड़ फिर 300 करोड़ दिया गया, मात्र यही राशि उपलब्ध कराया गया है, बिहार को उपलब्ध कराया है जिस

कारण उस कार्य में भी शिथिलता है लेकिन जितनी राशि प्राप्त हो रही है ग्रामीण कार्य विभाग को, उसके माध्यम से वह सड़कों के निर्माण का काम कर रही है, इसके अलावा सभापति महोदय मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अलावे जो 500 से लेकर 999 तक के आवादी वाले गांव की सड़कों का है वह भी मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सड़क निर्माण योजना के तहत जुट जायेगा(क्रमशः)

टर्न-40/10.3.2011/बिपिन

श्री प्रेम रंजन पटेल: कमशः लेकिन उससे कम आबादी वाली जो सड़कें होंगी वह छूट जाएगा । जो बसावट सर्वे भिलेज लिया जाता है, प्रधान मंत्री गांव रेवेन्यू भिलेज को लिए जाता है, जो बसावट है, टोले हैं जहां आबादी बसी है, वह सड़कें छूट जाती हैं । उसके लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, हमारे मुख्यमंत्री ने प्रारम्भ किया और उसके तहत सड़कों के निर्माण का कार्य चल रहा है । उसमें दिसम्बर 2010 तक 1471.21 करोड़ की लागत में 3,349.4 कि०मी० सड़कों का निर्माण अब तक हो चुका है । 2010-11 में उसमें 260 करोड़ का उपबंध किया गया था और 2011-12 में उसमें तीन सौ किलोमीटर, तीन सौ करोड़ रूपया का उपबंध किया गया है मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसके माध्यम से 11 सौ कि०मी० की सड़कों का निर्माण होना है । इसके तहत और भी कई योजनाओं के माध्यम से सड़कों का निर्माण हो रहा है । न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत 318.42 कि०मी०, 3018.42 कि०मी० जिसमें 27 पुल भी शामिल है 1,034.94 करोड़ की लागत से, नबार्ड ऋण योजना, जो हमको ऋण मिलता है नबार्ड के माध्यम से, उसके माध्यम से भी 1361.4 कि०मी० 758.11 करोड़ की लागत से यह काम हो रहा है ।

सभापति (श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह): माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें ।

श्री प्रेम रंजन पटेल: दो मिनट और कहना चाहता हूं सभापति महोदय ।

सभापति (श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह): नहीं, नहीं, अब आप समाप्त करें ।

श्री प्रेम रंजन पटेल : एक बहुत बड़ा हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया, विधायक निधि योजना को समाप्त करने का निर्णय लिया । बहुत बढ़िया काम किया । विधायक निधि के माध्यम से छोटे-छोटे काम होते थे लेकिन हमारे मुख्यमंत्री उसके माध्यम से विभाग के पदाधिकारी, विभाग के अधिकारियों के माध्यम से उसमें गड़बड़ियां होती थी, और बदनाम होता था जन-प्रतिनिधि होता था, विधायक बदनाम होते थे । उनके मान-सम्मान को बचाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री ने इतना बढ़िया निर्णय लिया है, इतना अच्छा निर्णय लिया है, मैं उसकी सराहना करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री ने जो नई योजना बनाई है मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना, उसके माध्यम से जो छोटी-छोटी योजनाएं हैं उन योजनाओं को ...

सभापति (श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह): माननीय सदस्य, अब आप बैठ जाएं । आप बैठ जाएं ।

श्री प्रेम रंजन पटेल : सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं को केवल रखना चाहता हूं । हमारे यहां दो सड़कें हैं जो पथ निर्माण विभाग के द्वारा अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव दिया हुआ है । ग्रामीण कार्य विभाग के जिम्मे है और उसको अभी तक ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा एन०ओ०सी० नहीं दिया गया है । सभापति महोदय, विभाग के मंत्री यहां बैठे हुए हैं मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि वह बहुत प्रमुख सड़क है उसको अगर एन०ओ०सी० दे देंगे तो पथ निर्माण विभाग के द्वारा अच्छी बढ़िया सड़क का निर्माण हो जाएगा उसके माध्यम से ।

सभापति (श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह): वह आप भेज दीजिए । मंत्री को भी दे दीजिए ।

माननीय सदस्य मोती लाल प्रसाद ।

व्यवधान ।

सभापति (श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह): माननीय सदस्य श्री मोती लाल प्रसाद । व्यवधान ।

सभापति (श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह): अब आप बैठ जाएँ। प्रेम बाबू बैठ जाएँ आप। व्यवधान।

माननीय सदस्य श्री मोती लाल प्रसाद। बोलिये। व्यवधान।
बोलिये, बोलिये। व्यवधान। बैठ जाइये, बैठ जाइये। बोलिये। व्यवधान। आप बैठ जाइये, बैठ जाइये। हो गया।

श्री मोती लाल प्रसाद: सभापति जी, ग्रामीण कार्य मंत्री माननीय डॉ० भीम सिंह द्वारा लाए गए अनुदान मांग के समर्थन में मैं खड़ा हूँ।

सभापति जी, जनता से ऐतिहासिक जनादेश प्राप्त करने के बाद वर्तमान सरकार का यह पहला बजट है और इस पहले बजट में आज जो ग्रामीण कार्य विभाग .. कमश:

श्री मोती लाल प्रसाद : ...क्रमशः... आज जो ग्रामीण कार्य विभाग ने अपना माँग रखा है, वह काबिले तारीफ है । सरकार गाँव के विकास के लिए, गाँव के उत्थान के लिए, गाँव को आगे ले जाने के लिये, ग्रामीण सड़कों का जाल बुनना चाहती है और हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार शरीर में नसों का महत्व होता है उसी प्रकार गाँव और राज्यों के समृद्धि में, उत्थान में सड़कों का महत्व होता है और इसी महत्व को समझते हुये विभाग ने जो बजट लाया है, जो उपबंध किये हैं, उसकी मैं तारीफ करता हूँ और समर्थन करता हूँ । सरकार की ओर से बहुत सारी योजनाएँ चल रही हैं और उन योजनाओं के माध्यम से पिछले पाँच वर्षों में १८ हजार कि०मी० से भी ज्यादा सड़कें बनायी गयी हैं दिसम्बर, २०१० तक और आगे भी सड़कों पर काम जारी है, २४,५०० कि०मी० सड़कों का निर्माण चल रहा है ।

आगामी पाँच वर्षों में यह सरकार विकास के लिए ज्यादा समर्पित रहेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि राष्ट्रीय परिदृश्य पर बिहार अपना महत्व कायम कर सके । वैसे भी, बिहार जब-जब जगा है, जब-जब अँगुवाई ली है तो बिहार ने एक बड़ी लकीर खींची है । इतिहास गवाह है कि बिहार के लोगों को, इस धरती के लोगों को जब-जब मौका मिला है तो अपने परिपक्व नेतृत्व से इस देश को, इस समाज को बहुत कुछ देने का काम किया है । इतिहास गवाह है, चन्द्रगुप्त मौर्य - इस धरती के लाल को जब मौका मिला और इस देश की जब अगुवाई की तो आज भारत का जो क्षेत्रफल है, उससे भी ज्यादा क्षेत्रफल पर उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया और उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था । उसके बाद शेरशाह सूरी को जब मौका मिला तो अपने पाँच साल से भी कम शासन करने के बावजूद उन्होंने जो इस देश को दिया, उसको आज भी लोग याद करते हैं, उन्होंने ग्रेण्ड टैंक रोड बनाया, उसके दोनों तरफ वृक्ष लगाये और डाक व्यवस्था चलायी । आज भी लोग शेरशाह सूरी का नाम लेते हैं । उसी प्रकार इस देश में प्रथम बार मौका मिला प्रथम राष्ट्रपति बनने का तो आदरणीय डॉ० राजेन्द्र बाबू ने बिहार और देश के जो केन्द्र बिन्दु थे, सोमनाथ मन्दिर के पुनरुद्धार का, तो उन्होंने सोमनाथ मन्दिर के पुनरुद्धार में महति भूमिका अदा की ।

सभापति (श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह) : माननीय सदस्य, आपका समय बहुत कम है, अब आप समाप्त करें ।

श्री मोती लाल प्रसाद : बिहार के लोगों को जब-जब मौका मिलता है तो वे अपना मजबूत पक्ष रखते हैं और न केवल समाज को बल्कि सम्पूर्ण देश को दिशा देने का काम करते हैं ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

आज आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, डॉ० भीम सिंह के नेतृत्व में जो योजनाएँ बनी हैं और काम चल रहे हैं, उससे मैं संतुष्ट हूँ और आप सभी को खास करके आदरणीय अध्यक्ष जी का मैं तहेदिल से शुक्रिया अदा करते हुये अपनी बात को समाप्त करता हूँ ।

श्री अवधेश कुमार राय : महोदय, मुझे भी बोलने का मौका दिया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अवधेश जी, आप कभी भी लिखकर आसन को नहीं देते हैं कि बोलेंगे । आगे से लिखकर आसन को दीजियेगा । श्री अवधेश कुमार राय ।

श्री अवधेश कुमार राय : अध्यक्ष महोदय, मेरे लिए समय निर्धारित बहुत कम है, इसलिए मैं अपने क्षेत्र की मूल बातों को कहूँगा। मैं सिर्फ एक-दो बातें रखूँगा, पहले अगर तिजोरी से खजाने की लूट हुई तो आज की तारीख में सड़क से खजाने की लूट हो रही है। महोदय, मुख्यमंत्री सड़क योजना से हमारे रिपोर्ट के अन्दर माननीय मंत्री जी ने पेश किया है ४३४९ कि०मी० सड़क बनी है, कमप्लीट हुई है। महोदय, सिर्फ अगर जाँच करवा लिया जाय तो ५० परसेंट कार्य पूरा नहीं होता है और उसको कमप्लीट बता दिया जाता है। हम सिर्फ मंत्री जी को अपने क्षेत्र का बछवाड़ा-समसा पथ एक है, काम पूर्ण दिखा दिया गया और उसकी आप सिर्फ जाँच करवा लीजिए, ढाई करोड़ में एक करोड़ भी खर्च नहीं हुआ, आप सिर्फ एक योजना की जाँच करवा लीजिए और इस तरह की लूट बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट है, कैसे लूटता है, उसको आप देखियेगा। उसी तरह से जिस पथ के बारे में चौड़ीकरण के बारे में हमारे माननीय सदस्यों ने कहा, एम०एम०बी०पथ, महनार-महदीनगर-बछवाड़ा पथ में भी कार्य हुए हैं, पथ बने हुए ४ साल भी नहीं हुए और पथ टूट गया। आप इसकी जाँच करवा लीजिए। अभी भगवानपुर के अन्दर बन रहा है पुल बहसी-भगवानपुर घाट पर तो आप उस पुल की गुणवत्ता की जाँच करवा लीजिए और मेरे क्षेत्र में लगभग दो दर्जन ऐसे पथ हैं, जिस पथ में काम किसी में ३ साल पहले मिट्टी पड़ा, मिट्टी पड़ा हुआ है। हम यह सब लिखकर दे देंगे मंत्री जी। हम यह सिर्फ कहना चाहेंगे कि अगर आप कुछ योजना बनाने का और लागू करने का ग्रामीण जीवन में गरीबों के बस्ती तक पहुंचाने की मंशा रखते हैं तो इंजीनियरिंग लूट जो है, भ्रष्टाचार जो है और सड़कों पर से जो पैसे बटोरे जा रहे हैं, इस लूट को यदि आप बन्द कर दीजियेगा, तब ही आप विकास की बात कर सकते हैं, नहीं तो अभी बदस्तूर जैसे चल रहा था, वैसे आज भी चल रहा है, लूट बरकरार है और मैं अन्त में एक मिनट में ही अपनी बातों को कहना है, इसलिए दो-तीन मांग आपके सामने रखते हुए आपका ध्यान आकृष्ट करूँगा। रसीदपुर घाट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पुल वहां बनना चाहिए, तेनुआघाट रातगांव वाया नदी में जो तेघड़ा विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है और वाया के अन्दर चौथा में एक सौ वर्ष पहले पुल बना था, वह पुल अब टूटने के हालात में है और उससे समस्तीपुर, बेगूसराय जिले का लगभग ५० हजार से ज्यादा आबादी इससे आवागमन करती है, उस पुल का निर्माण आप करवाने की कृपा करें। पिछड़ा हुआ इलाका जो बछवाड़ा का है, वह दियारा का क्षेत्र बछवाड़ा से शुरू होता है और समस्तीपुर सीमा तक वह रोड जाती है, उस रोड को बनाने के लिए बछवाड़ा-घमटिया से लेकर के चमथा घाट तक सड़क बनवाने की हम आपसे अपील करते हैं और हम आशा करेंगे कि गुणवत्तापूर्ण कार्य के लिए आप कोई योजना, कोई कार्यक्रम बनायेंगे और तिजोरी से लूट की जगह सड़क से लूट हो रही है, उसको रोकने की दिशा में आप कदम बढ़ायेंगे। यही कहते हुए अध्यक्ष जी ने जो समय दिया, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़कों का बिहार में निर्माण हो रहा है, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है । लेकिन १९७१-७२ में यहां विरोध पक्ष के नेता के रूप में बैठे हुए थे स्वर्गीय दारोगा प्रसाद राय जी और सरकार के कोई मंत्री बजट भाषण पर अपना उत्तर दे रहे थे तो जो गुणवत्ता की बात इन्होंने उठायी, उसी पर एक बात उन्होंने रखी थी दारोगा राय प्रसाद जी ने ।

..... क्रमशः

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : क्रमशः.....दरोगा प्रसाद राय जी ने, उन्होंने भोजपुरी की एक कहावत कही "ताला लगल बा आ पीछे पाला खुलल बा" मैं इतना ही कहना चाहूंगा सड़कें बनें, लेकिन उनकी गुणवत्ता पर ध्यान रखा जाय। सड़कें तो आज बनती हैं, लेकिन कल होकर उखर जाती हैं तो निश्चित तौर से इस बात का ध्यान रखा जाय और आंगनबाड़ी केन्द्र है बिहार में हजारों वह सारे के सारे आंगनबाड़ी केन्द्र ८० प्रतिशत से ज्यादा आंगनबाड़ी केन्द्र बंद पड़े हैं, उनको चलाने का प्रयास किया जाय। इतना ही कहना चाहता हूँ।

अध्यक्ष : अब सरकार का उत्तर, माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग।

सरकार का उत्तर

श्री भीम सिंह, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट सत्र है, हालांकि संविधान में बजट शब्द का उपयोग नहीं हुआ है, यह तकनीकी रूप से आय-व्ययक विवरणी कही जाती है, लेकिन जो बोलचाल की भाषा है उसी भाषा को मान लिया जाय तो बजट सत्र है और इस बजट सत्र में हमारी सरकार की ओर से जिसके नेता बिहार के लोकप्रिय नेता श्री नीतीश कुमार जी हैं उस सरकार की ओर से हमारे द्वितीय नेता आदरणीय उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी ने सदन में बजट प्रस्तुत किये थे और उस बजट के आलोक में जो अनुदान मांगे हैं और उन अनुदान मांगों के सन्दर्भ में जो कटौती प्रस्ताव आये हैं उससे यह आज का वाद-विवाद हो रहा है, विमर्श हो रहा है जिसपर मुझे सरकार की ओर से उत्तर देने का अवसर मिला है। महोदय, देश में, प्रदेश में जनतांत्रिक व्यवस्था है और जनतांत्रिक व्यवस्था कैसे संचालित हो इसके लिए अनेक विद्वानों ने, संविधान में व्यवस्था की है। हम कॉल एंड शकधर को देखें कॉल और शकधर की जो संसदीय पद्धति और प्रक्रिया है उसको महोदय हमने देखा है कि विपक्ष के माननीय सदस्यों को अधिकार है कि वह सरकार के अनुदान मांगों पर कटौती प्रस्ताव लायें उन्हें अधिकार है। हमने देखा है कॉल एंड शकधर ने लिखा है कि यह कटौती प्रस्ताव तीन प्रकार के होते हैं। पहला- नीति अननुमोदन कटौती पौलिसी को डिनाउंस करती है। आप हमारी नीति को नहीं मानते उसका अनुमोदन नहीं करते हैं। इस सन्दर्भ में कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। दूसरा प्रस्ताव मितव्ययिता का कटौती प्रस्ताव होता है जिसमें माननीय सदस्य पेश करते हैं सरकार के समक्ष सुझाव पेश करते हैं कि कैसे मितव्ययिता बरते और तीसरा है- सांकेतिक कटौती यह प्रस्ताव उस समय आता है, जब सरकार किसी विशेष नीति के सन्दर्भ में विफल हो गयी हो उसकी ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए यह कटौती प्रस्ताव विपक्ष के सदस्य की ओर से आता है। मुझे आश्चर्य है जब मैं कटौती प्रस्ताव के मूवर माननीय सदस्य श्री सम्राट चौधरी जी की ओर से और विपक्ष की ओर से माननीय वरिष्ठ सदस्य जो इस राज्य के शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं श्री रामलक्षण राम रमण जी, जब बोल रहे थे तो उनकी बातों को सुनकर लगा कि यह कटौती प्रस्ताव का औचित्य नहीं है। आप गौर करेंगे इनके भाषण में किसी भी तरह की न नीति वक्तव्य, न हमारा विरोध करते हैं कि हम कौन सी नीति पर चाहते हैं संशोधन उसके बारे में कुछ नहीं कहा। इन्होंने मितव्ययिता के बारे में कुछ नहीं कहा।